स्वदेशी पत्रिका

वर्ष-16, अंक-7, आषाढ़-श्रावण- 2065, जुलाई, 2008

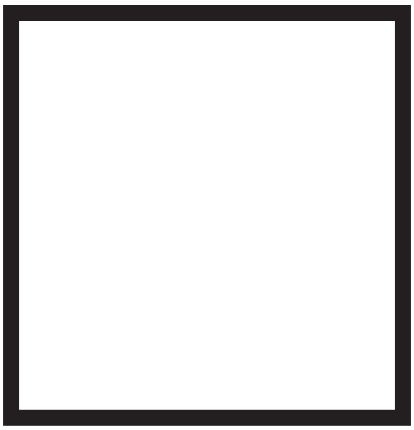

वामपंथियों की समर्थन वापसी के बाद

यूपीए में भगदड़

विक्रम उपाध्याय

9

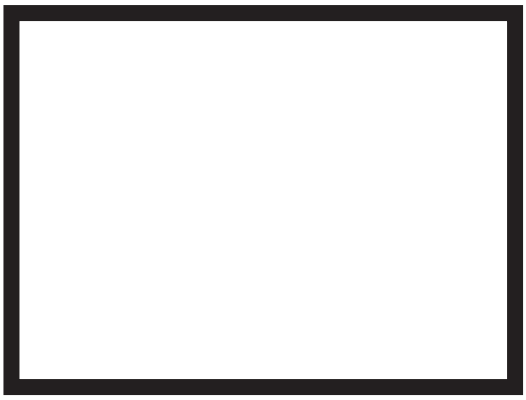

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था वामदलों की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

13

महंगाई कम करने के उपायों का दस्तावेज हमने यूपीए को बहुत पहले ही दे दिया था। लेकिन सरकार ने उस पर अमल नहीं किया : बर्धन

अ नु क्र म

आवरण लेख
महंगाई और कूटनीतिक कमज़ोरी है सरकार की उपलब्धि : गुरूमूर्ति 11

संस्कृति
क्या गंगा लुप्त हो जायेगी?
- निरंकार सिंह 14
प्राणों की बाजी लगाकर भी गंगा को बचाएंगे
- जी.डी. अग्रवाल 17

संरक्षण
भारतीय संस्कृति और पर्यावरण
- डॉ विजय वशिष्ठ 19

आंदोलन
सरकार किसानों के हितों की चिंता करे
- राजन चब्बा 21

कृषि
बढ़ते कृषि मूल्यों पर अमीर देशों का कुतर्क
- डा0 भरत झुनझुनवाला 24

सेज
सब्सिडी के बोझ तले दबी सरकार
- रुद्रदत्त 27

पाठकनामा 2

समाचार परिक्रमा 4

आर्थिक विश्व 8

संपादक : **विक्रम उपाध्याय**

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022
से प्रकाशित दूरभाष : 011-26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 से मुद्रित।

टंकण एवं सज्जा : **प्रेम जोया**

पाठकनामा

संविधान को बदलना ही चाहिए

स्वदेशी पत्रिका के पिछले अंक में 'संविधान की अवहेलना' शीर्षक से प्रकाशित डॉ. रमाकांत पांडे का लेख अपने आम में परिपूर्ण था। खाद्य संकट, सट्टा बाजार और स्वदेशी वृतांत अच्छे थे, उससे मंच के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलेगी। संविधान की टिप्पणी पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा संविधान ही बहुसंख्यक समाज के खिलाफ है।

संविधान ने सिर्फ व्यक्तिगत अधिकार और कर्तव्य बहुसंख्यक समाज के उपर थोपे हैं। हम हमारे धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। संगठन बनाया तो उसे जातिवादी कहा जाता है। ऐसे संविधान को बदलना ही चाहिए। भाजपा जब सत्ता में थी उस वक्त धारा 370 को सरकार के ऐजेडे से ही बाहर कर दिया गया। संसद में बहुसंख्यक समाज के हित में कोई भी बात नहीं करता। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे महापुरुष, रामायण और महाभारत जैसे हमारे ग्रंथ हसी के पात्र बना दिए गए हैं।

चैनलों पर उनके बारे में हास्य व्यंग्य दिखाया जाता है। अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता पर कुठाराघात बता दिया जाता हैं। हिंदू संस्कृति, हिंदूधर्म, हिंदू आचार्य, हिंदू पुराण बहुसंख्यक समाज में आदरणीय हैं। बहुसंख्यक हिंदू समाज के गौरव को ठेस पहुचाने के बावजूद हिंदू शांत और संयमी है, पर सीमा से अधिक कुठाराघात हुआ तो एक क्रांति की ज्वाला भी निकल सकती है।

महाराष्ट्र में ऐसे ही एक नाटक के खिलाफ विरोध शुरू हुआ है। अभी तो यह चिंगारी है यदि सरकार नहीं चेती तो आग भी भड़क सकती है। संसद में बैठे संदस्यों को जिम्मेदारी के साथ बहुसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को ढंग से उठाना चाहिए, चाहे वे हुसैन हों या दूसरा कोई भी। मंदिर अधिग्रहण, हिंदू संस्थाओं का सरकारीकरण, ऐसी घटनाएं इस देश में चल रही हैं जो राष्ट्रहित में नहीं है। इसलिए संविधान को बदले बिना इस तरह की घटनाओं को रोक पाना संभव नहीं लगता।

अशोक मुले, महाराष्ट्र

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क ***'स्वदेशी पत्रिका'*** दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

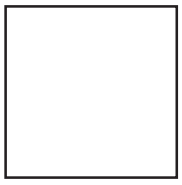

भाजपा को यह कभी स्वीकार्य नहीं कि अगर भारत को कोई एटमिक टेस्ट करना हो तो उसे अमरीका सहित अन्य देशों की इजाजत लेनी पड़े, जबकि यह देश ऐसे कई पड़ोसी देशों से धिरा हुआ है जिनके पास भारी मात्रा में परमाणु हथियार हैं।

राजनाथ सिंह
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

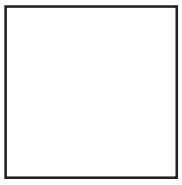

डॉ• मनमोहन सिंह गलत समय पर बनाए गए गलत प्रधानमंत्री हैं। वे वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं, किंतु कुशल प्रशासक नहीं।

उमा भारती
भारतीय जनशक्ति की अध्यक्ष

तब और अब

जिस तरह बुश ने सद्दाम को खत्म किया उसी तरह सोनिया गांधी भी सपा सरकार को हर हाल में खत्म करने पर तुली हुई है।

अमर सिंह , कांग्रेस और सपा के बीच छिड़ी लड़ाई के दौरान

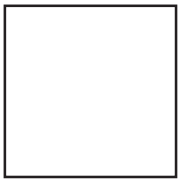

सोनिया गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्षा और उच्चे कद की नेता है। संसद में समाजवादी पाटी का एक–एक वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ेगा।

कांग्रेस से नई दोस्ती के बाद
माकपा नेता

सपा की सौदेबाजी

वाम दलों द्वारा समर्थन वापसी के बाद यह सवाल स्वाभाविक है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की यह सरकार कितने दिन चलेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के अचानक उपजे कांग्रेस प्रेम ने कुछ हद तक उन अटकलों को थाम लिया है कि देश में शीघ्र ही आम चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस बाहरी तौर पर यह दिखाने की कोशिश भी कर रही है कि सरकार को कोई खतरा नही हैं, लेकिन यह सभी जानते हैं कि कांग्रेस और सपा का मेल स्वाभाविक नहीं है। सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देने वाले मुलायम आखिर क्यों उन्हीं के लिए फिर से सत्ता के लिए रास्ता बनाने का प्रयास करेंगे। उत्तरप्रदेश में कांग्रेस अपनी जड़े तलाशने में जुटी है। राहुल गांधी पर कांग्रेस का दारोमदार है। कांग्रेस उन्हें अपना परिपक्व नेता बनाने का जतन कर रही है। सपा की नजर में वह अभी बच्चे हैं। कांग्रेस को भी अपनी स्थिति सुधारने के लिए अल्पसंख्यक वोट चाहिए, मुलायम उत्तरप्रदेश में मुसलमानों को अपनी जायदाद मानते हैं। वंचित वर्ग पर मायावती का असर सबसे अधिक है, वोट तोड़ने या जोड़ने की हर संभावना पिछड़े वर्ग के बीच ही है। उत्तरप्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच आखिर कौन सा कॉमन एजेंडा होगा जहां वे दोनों पार्टियां एक साथ खड़ी होंगी। यदि कांग्रेस ने मुलायम को लोकसभा चुनाव में वाक ओवर दिया तो वह अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेगी। इस तरह के राजनीतिक फैसले कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं होगा। मनमोहन सिंह की सरकार ने देश को जिस हालात में ला खड़ा किया है वहां से निकलना किसी भी नई सरकार के लिए आसान नहीं होगा। जनता महंगाई से टूट चुकी है। वह कांग्रेस का हिसाब करने के लिए बेसब्र है। ऐसे में इस गठबंधन में कोई पार्टी आकर जनता का कोपभाजन बनने के लिए शायद ही तैयार होगी। सपा के ही एक सांसद ने राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण कराया उसमें यह निष्कर्ष निकला कि देश के लगभग 70 फीसदी लोग महंगाई को चुनावी मुद्दा मानेंगे। यदि सपा यह तर्क देती है कि देशहित में परमाणु समझौते की खातिर वह मनमोहन सिंह की सरकार बचाने का हर संभव प्रयास करेगी तो जनता उसे भी महंगाई के लिए बराबर का दोषी मानेगी। लोगों के लिए आज भी परमाणु समझौते से कहीं अधिक रोटी महत्वपूर्ण है। सपा के नेता यह जानते हैं। परंतु अपने पिछले शासन काल के दौरान किए की कलई खुलने से सपा नेता डर ने लगे हैं। उन्हें फिलहाल मायावती का डर सता रहा है। उन्हें एक तरह से राजनीतिक शरण चाहिए जो मौजूदा केंद्र सरकार ही दे सकती है। राज्य और केंद्र दोनों में अपने विरोधियों की सरकार होने के कारण सपा का बौखलाहट बढ़ गया था। एक तरफ सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का खौफ था तो दूसरी तरफ मायावती द्वारा राजनीतिक बदले की कार्रवाई का डर। ऐसे में सपा के लिए कांग्रेस द्वारा किए गए अपमान को भुलाकर समर्थन के बदौलत राहत पाना ही बेहतर विकल्प था।

कांग्रेस किसी तरह अपनी सरकार बचा लेती है तो भी उसके सामने उपजी समस्याएं कम नहीं होने वाली। महंगाई और बढ़ती मुद्रा स्फीति की दर जहां उसके जनाधार को तेजी से खाती जा रही हैं वहीं राजनीतिक रूप से भी वह गठबंधन के अन्य सहयोगियों के लिए अनउपयोगी भी होती जा रही है। खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और द्रमुक की त्योरियां अभी से चढ़ने लगी है। द्रमुक प्रमुख करुणानिधि अभी भी इस पक्ष में हैं कांग्रेस वामदलों के प्रति उदासीनता का रुख छोड़ मेलमिलाप की नई कोशिश करे। द्रमुक नेता जानते हैं कि महंगाई और परमाणु मुद्दे पर सरकार से अलग होने के बाद वामपंथी अगले चुनाव में इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाएंगे और इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत गठबंधन में शामिल किसी भी दल के लिए जवाब देना आसान नहीं होगा। राष्ट्रवादी पार्टी भी आगामी लोकसभा चुनाव में किसी और के साथ जाने की संभावना तलाश रही है। शरद पवार कांग्रेस के कुछ खास नेताओं से बेहद नाराज हैं, जिन्होंने बढ़ती महंगाई के लिए कृषि मंत्री को ही सीधे जिम्मेदार ठहरा दिया।

जनता यह जानना चाहती है कि आखिर यह महंगाई कब और कहां जाकर रूकेगी। विशेषज्ञों की माने तो महंगाई का यही स्तर बना रहा तो उपलब्धि होगी। न तो अतंरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में कोई कमी आने वाली है और न खाद्यान्न की कीमत गिरने वाली है। रबी और खरीफ का सरकारी खरीद मूल्य हजार रुपये के आसपास करने के बाद खुले बाजार में इससे कम कीमत पर अनाज उपलब्ध होने का सवाल ही नहीं है। विशेषज्ञ सरकार को यह सलाह दे रहे हैं कि कीमतों को नीचे लाने के बजाय गरीबों की आमदनी बढ़ाने के उपायों पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए।

दुनिया ने माना गोमूत्र चिकित्सा का लोहा

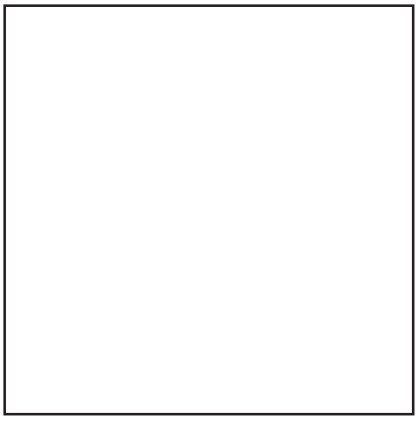

अब भारत ही नहीं दुनिया के कई अन्य देश भी गोमूत्र चिकित्सा का लोहा मानने लगे हैं। गो मूत्र से बनी पेटेंट औषधियों की मांग अमरीका, पाकिस्तान, कनाडा और दुबई से भी आ रही है। खासकर एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों में गोमूत्र चिकित्सा का असर काफी चौकाने वाला रहा है। दमा जैसे रोग के निदान का दावा भी गोमूत्र चिकित्सा पद्धत्ति में किया गया है। अमरीका में गोमूत्र चिकित्सा पद्धति पर अपना शोध पत्र पढ़ने वाले इंदौर के गोमूत्र चिकित्सा और अनुसंधान केन्द्र के निदेशक डॉ. वीरेन्द्र कुमार जैन व रेखा जैन के अनुसार गो–मूत्र एडस, कैंसर के अलावा डच्च रक्त चाप, हृदय रोग, यौन दुर्बलता, गठिया, स्पॉन्डोलाईटिस, स्त्री रोग, चर्म रोग, यकृत, पेट और गुर्दे की बीमारियो, पथरी अम्लता, गैस आदि बीमारियों का उपचार संभव हुआ है और तीन लाख से अधिक मरीज पंचगव्य से बनाई औषधियों का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। कितनी विडबंना है कि पूरी दुनिया में गोरस और गोमूत्र की उपयोगिता सिद्ध हाने के बावजूद गोकसी रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है।

उद्योग जगत भी बोला, हाय महंगाई

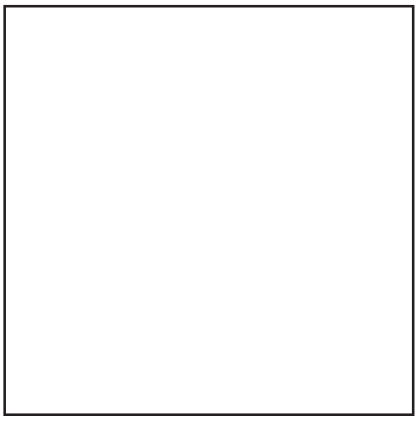

आसमान छूती महंगाई आम आदमी को ही परेशान नहीं कर रही है, बल्कि इसकी आंच अब उद्योगपति भी महसूस करने लगे हैं। किसान, मजदूर, नौकरीपेशा व, व्यापारी वर्ग के साथ साथ उद्योग जगत को भी महंगाई का भय सता रहा है। घरेलू उद्योगपतियों को ऐसा लगने लगा है कि बढ़ती महंगाई के कारण उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। फिक्की के तिमाही बिजनेस कांफिडेंस सर्वेक्षण में शामिल 64 फीसदी उद्योगपतियों ने स्वीकार किया कि पिछले छह महीने में अर्थव्यवस्था के हालात काफी खराब हुए हैं। ब्याज दरों में वृद्धि से स्थिति और बिगड़ सकती है। उद्योगपतियों का ऐसा मानना है कि महंगाई की दर 2008 में पूरे वर्ष अधिक ही रहेगी। जो उद्योगपति थोड़े–बहुत सुधार की उम्मीद करते हैं उनका भी यही कहना है कि महंगाई इतनी कम नहीं होगी कि अर्थव्यवस्था चैन की सांस ले सके। उद्योगपतियों के अनुसार कच्चे माल की लागत का बढ़ना स्वाभाविक है, इसी के चलते तमाम मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों की खुदरा कीमतों में वृद्धि हुई है। फिक्की का अनुमान है कि अर्थव्यव्स्था में पिछले कुछ वर्षो से जारी तेजी की रफ्तार भी अब सुस्त पड़ने लगी है। स्थिति के सुधरने की गुंजाइश भी उद्योग समुदाय को नहीं है।

स्वदेशी महिलाएं पुरूषों से कमतर नहीं

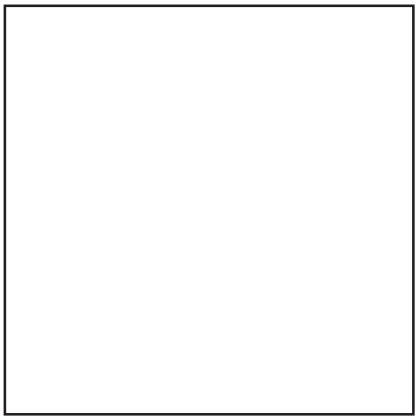

'स्वदेशी और स्वावलंबन में महिलाओं की भागीदारी' विषय पर रांची महानगर के प्रांत में आयोजित परिचर्चा में मुख्य अतिथि श्रीमती माया वर्मा (पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय महिला परिषद) ने कहा है कि स्वदेशी से जुड़े मामलों में महिलाएं आज पुरूषों से किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं हैं। इसके साथ ही मुख्य अतिथि ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वदेशी एक स्वाभाविक भावना है, जिसे महिलाओं द्वारा ही संस्कारित किया जा सकता है। प्रमुख वक्ता महेंद्र कॉलेज के प्रोफेसर एवं स्वदेशी जागरण मंच रांची के विभाग संयोजक प्रो. गोपाल प्रसाद सिन्हा ने कहा कि स्वदेशी तकनीक हमारे देश के स्वावलंबन का आधार है, जो प्राचीन काल से इस देश में स्थापित है। परिचर्चा कार्यक्रम के इस मौके पर कुंज बिहारी ने स्वदेशी पर आधारित एक कविता सुनाकर जहां सभी को भावविभोर किया, वहीं विकास भारती की रंगना चौधरी ने जननी जन्म भूमि की अवधारणा की व्याख्या कर लोगों में स्वराष्ट्र की भावना का संचार किया। श्री चंद्र प्रकाश ने कहा कि धार्मिक

और वैचारिक संघर्ष ने हमारी प्राचीन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हैं। मंच के कोषाध्यक्ष श्री चिरंजी लाल अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही इंदु पराशर ने महिलाओं का आह्वान किया कि वे बाजारवादी संस्कृति को रोकने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का ही अधिक से अधिक उपयोग करें। महानगर के सह संयोजक श्री मिलन बोस ने अपने धन्यवाद भाषण में यह संकेत दिया कि स्वदेशी के माध्यम से देश की संस्कृति के अस्तित्व को बचाना ही आज मुख्य चिंता का विषय है। कार्यक्रम में राज्य अभियंता भार्या संघ, संस्कार भारती और सेवा भारती की महिलाओं की उपस्थिति ने स्वदेशी जागरण मंच की विचारधारा को और अधिक मजबूती प्रदान की।

आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को आठ से बढ़ाकर साढ़े आठ प्रतिशत कर दिया है। रिजर्व बैंक के इस कदम का सीधा असर यह होगा कि अब बैंकों से होम लोन से लेकर पर्सनल लोन प्राप्त करने वालों को अधिक ब्याज देना होगा। जानकारों का मानना है कि आर बी आई के इस फैंसले से उन लागों की दिक्कतें बढ़ जाएंगी, जो होम लोन को ब्याज के साथ लौटा रहे हैं और जो अपने घर को खरीदने के लिए होम लोन लेना चाह रहे हैं। बैंक अब अपने होम लोन को महंगा कर देंगे। मुद्रा स्फीति की दर के 13 साल के रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद आर बी आई के पास रेपो रेट बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। आरबीआई ने यह फैसला अकस्मात नहीं लिया है बल्कि पिछले कई दिनों से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मुद्रास्फीति के बोझ से दबी जा रही सरकार को राहत देने के इरादे से रिजर्व बैंक अवश्य ही इस तरह का कोई कदम उठाएगा।

म्यांमार से आर्थिक समझौता

विश्व व्यापार संघ में चल रहे गतिरोध ा के चलते भारत ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी के तहत भारत ने म्यांमार के साथ चार आर्थिक सहयोग समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। म्यांमार की राजधानी रंगून में समझौतों पर हस्ताक्षर करने के वक्त वाणिज्य एवं ऊर्जा राज्य मंत्री जयराम रमेश और म्यांमार के राष्ट्रीय योजना एवं आर्थिक विकास मंत्री यू सू था भी मौजूद रहे। दोनों देशों के बीच पहला समझौता द्विपक्षीय निवेश संवर्धन को लेकर हुआ है। फैसले के मुताबिक परस्पर देशों की कंपनियों को निवेश में अतिरिक्त सहूलियतें प्रदान की जाएंगी। दूसरा समझौता भारतीय एक्जिम बैंक और म्यांमार विदेश व्यापार बैंक के बीच 6.40 करोड़ डॉलर की क्रेडिट लाईन को लेकर है। इसके जरिए पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन की ओर से म्यांमार में तैयार की जा रही 230 केवी ट्रांसमिशन लाईन का वित्त पोषण किया जाएगा।

महंगाई के बावजूद सरकार को 9 फीसदी विकास की आशा

बढ़ती महंगाई और कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के बावजूद योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलुवालिया को उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाली भारी बढ़ोत्तरी के बावजूद भारत के लिए नौ प्रतिशत की विकास दर कायम रख पाना संभव है। उपाध्यक्ष के अनुसार हालांकि ऐसा करना कठिन है और इसके लिए हमें तेल की कीमतों पर नियंत्रण के प्रयासों के अलावा तेल पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए ऊर्जा के अन्य विकल्पों पर अपनी निर्भरता बढ़ानी होगी। पत्रकारों से बातचीत करते वक्त मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने यह स्वीकार किया कि बढ़ती महंगाई एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसके लिए हमें मध्यम स्तरीय लक्ष्यों से डिगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत ने पिछले तीन साल में 9 प्रतिशत विकास दर को छुआ है। श्री आहलुवालिया के इस दावे पर अर्थशास्त्रियों ने प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहा है, कि इस वित्त वर्ष में इस दर को कायम रखना संभव नहीं होगा। मोंटेक के अनुसार योजना आयोग का मानना है, कि अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा तोड़े बिना तेल की बढ़ती कीमतों के दुष्प्रभाव वाली स्थिति से निपटा जा सकता है।

परमाणु सामग्री की तस्करी बंद नहीं

अमरीकी ऊर्जा विभाग का दावा है कि परमाणु सामग्री की तस्करी के सामने आने के बावजूद अमरीका सरकार ने इसे आतंकवादियों की पहुंच से दूर रखने के प्रयास नहीं किए। उनका मानना है कि हथियार आतंकवादियों के हाथ लगें, इससे पहले ही हमें देश के नियंत्रण से बाहर

मौजूद परमाणु सामग्री को हासिल कर लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार वर्ष 1993 से अब तक परमाणु तस्करी के 300 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 19 मामले हथियार तैयार करने लायक स्तर के यूरेनियम और प्लूटोनियम की तस्करी के हैं, जिनका इस्तेमाल या तो युद्ध के समय पारंपरिक परमाणु शस्त्रों के तौर पर अथवा विस्फोटों के रूप में हो सकता है। ज्ञात हो कि महज कुछ किलोग्राम प्लूटोनियम एक परमाणु हथियार बनाने के लिए काफी है। इसलिए अमरीका को चाहिए कि वह परमाणु सामग्री की तस्करी बंद करने के प्रयास करे।

महंगाई पर उपराष्ट्रपति ने उठायी सरकार पर उंगली

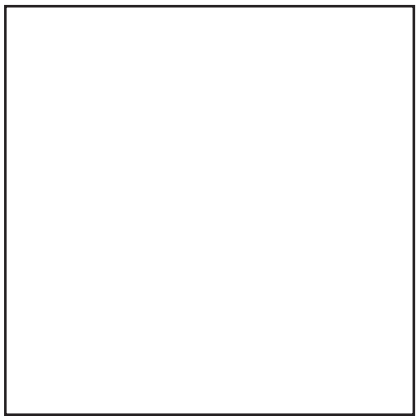

देश की सरकार महंगाई और कीमतों में बढोत्तरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार को कारण बताकर भले ही अपनी जवाबदेही से बचने का प्रयास करे लेकिन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने यह कहकर कि दुनिया इस समय कृषि वस्तुओं की कीमतों में अभूतपूर्व बढोत्तरी से दो–चार हो रही है, जिसका सीधा असर गरीबों पर पड़ रहा है, केन्द्र की यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि सुधार और ग्रामीण विकास के मुद्दे राजनीतिक प्रकृति के होते हैं। आर्थिक और सामाजिक हस्तक्षेप जरूरी है, लेकिन यह इतना होता नहीं कि अपेक्षित परिणाम सामने आ सकें। उन्होंने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का पुनर्वितरण, विकास में गांवों और गांव के गरीबों का शामिल करना, ग्रामीण इलाकों में संसाधनों व रोजगार तक पहुंच बढ़ाना, गैर–कृषि ग्रामीण गतिविधियां, शिक्षा, प्रशिक्षण और कृषि सुधार आज भी आम तौर पर एशिया और खास तौर से भारत में गरीबी का ग्रामीण चेहरा है। ग्रामीण विकास और गरीबी मिटाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

कश्मीर मुद्दा सुलझाए बगैर शांति नहीं : गिलानी

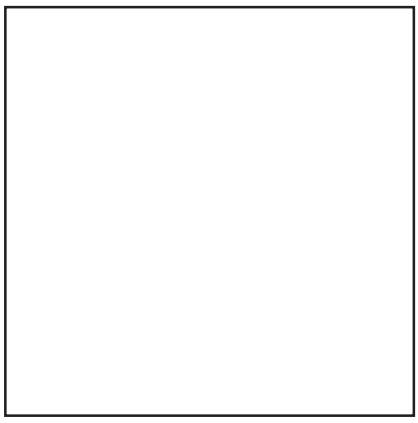

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने कश्मीर मुद्दे को अपनी सरकार की विदेश नीतियों के लिए नींव का पत्थर मानते हुए दावा किया है कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाए बिना दक्षिण एशिया में शांति संभव नहीं है। प्रधानमंत्री श्री गिलानी ने कहा कि इस मामले में तुरंत और दीर्घकालिक समाधान के लिए संवाद प्रक्रिया में कश्मीरी जनता के वास्तविक प्रतिनिधियों को शामिल करने की आवश्यकता है। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक से एक मुलाकात के समय पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि कश्मीर मुद्दे के कारण ही पिछले छह दशकों से भारत–पाकिस्तान के आपसी रिश्तों में खटास रही है। गिलानी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान बातचीत के जरिए कश्मीर समस्या के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखता है तथा जनाकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए समस्या का शीघ्र एवं शांतिपूर्ण हल चाहता है, और भारत से भी सकारात्मक रुख की उम्मीद करता है।

फ्रांस की सामरिक पेशकश

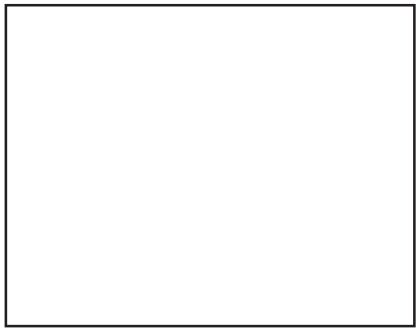

फ्रांस की शीर्ष हथियार निर्माण कंपनी नैक्टर के शीर्ष अधिकारियों ने पेशकश की है कि वे भारतीय सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रोद्योगिकी के हस्तांतरण, लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता वाली तोपें और बारूदी सुरंग निरोधक एवं उच्च गतिशीलता वाले वाहन विकसित करने को तैयार हैं। जमीनी लड़ाई के लिए जरुरी अग्रणी प्रणालियों के निर्माण संबंधी भारतीय सेना के हथियार विकास कार्यक्रम में पूर्ण भागीदारी की यह पेशकश ऐसे समय में की गई है जब भारतीय सेना आतंकवादियों और माआवादियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 155 एम एस की 2000 से 3000 तोपें तथा 1000 से 2000 बारुदी सुरंगें निरोधक लड़ाकू वाहन हासिल करने के लिए निविदा जारी करने की योजना बना रही है। विशेषज्ञों के अनुसार यह निविदा पांच से सात अरब यूरो मूल्य की हो सकती है और इसकी आपूर्ति में तीन

से पांच साल का समय लग सकता है।

देर आए दुरुस्त आए

'देर आए दुरुस्त आए' की तर्ज पर अमरीका को शायद अब समझ आया है कि सांप को कितना ही दूध पिलाओ, मौका मिलते ही वह दूध पिलाने वाले को भी डसने से नहीं चूकता। जिस आतंकवाद के लिए अमरीका बहुत समय तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का सहयोग करता रहा आज वही आतंकवाद दोनों देशों के बीच खटास पैदा होने का कारण बन चुका है। आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2001 में छेड़ी गई जंग में अमरीकी सहयोगी बनने के बाद से पाकिस्तान के अमरीका के साथ संबंध सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई के बयान के बाद दोनों देशों के बीच संबंध काफी कटु हो गए हैं। इस्लामाबाद में राजनीतिक हलकों का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान की सीमा के भीतर आतंकियों के खिलाफ गठबंधन सेना द्वारा अभियान चलाए जाने की अमरीकी मांग मुख्य समस्या है क्योंकि अमरीका की इस मांग पर पाकिस्तान कड़ा विरोध प्रकट कर चुका है। हवाई हमलों में पाक सीमा क्षेत्र में कई लोगों को मारा जाना अमरीका और पाकिस्तान के संबंधों में खटास का ही कारण है।

स्वामी राघवेश्वर भारती ने कहा

देव तुल्य हैं संघ के स्वयंसेवक : भारती

रामचंद्रपुरा मठ, शिमोगा (कर्नाटक) के गोवर्ण पीठाधीश्वर स्वामी राघवेश्वर भारती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को देवी–देवताओं का स्वरूप बताते हुए कहा कि भगवान राम और कृष्ण की तरह ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ राष्ट्र और धर्म हित में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण द्वारा रचित भगवद गीता के श्लोक 'यदा यदा ही धर्मस्य.....' का उल्लेख करते हुए स्वामी राघवेश्वर भारती ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को साक्षात भगवान की छवि बताते हुए कहा कि भगवान संघ के रूप में अवतरित हुए हैं। नागपुर में आयोजित तृतीय संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में मुख्य अतिथि स्वामी राघवेश्वर भारती ने प्रशिक्षु स्वयं सेवकों से गो हत्या पर रोक लगाने, जैविक तथा गो आधारित खेती पर ध्यान देने, वास्तविक 'धर्मनिर्पेक्षता' को व्याख्यापित करने, देश और धर्म की रक्षा के लिए मठ की दीवारों से बाहर निकल कर हिंदुत्व भाव से काम करने एवं आजीवन स्वयंसेवक बने रहने का संकल्प लेने का आह्वान किया है।

एन सी ई आर टी पढ़ा रही है–

'मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा'!

देश में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम तय करने तथा पुस्तकें प्रकाशित करने वाली सर्वोच्च शैक्षिक संस्था 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद' (एन. सी ई आर टी) अपनी पुस्तकों में पढ़ा रही है कि इस देश के मुसलमानों को हिंदुओं से जानमाल का खतरा है। खतरा सिद्ध करने के लिए एन. सी ई आर टी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में एक पाठ शामिल किया है, जिसमें मुसलमानों की अनेक समस्याओं के साथ ही यह भी पढ़ाया जा रहा है कि इस देश के मुसलमानों को हिंदुओं से जानमाल का खतरा है। 'मुसलमान और हाशियाईकरण' (अशक्तिकरण) 'मुस्लिम एण्ड मार्जिनताइजेशन नामक इस पाठ में सच्चर कमेटी की रपट का विस्तार से उल्लेख किया गया है। पाठ के प्रश्न क्रमांक पांच में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से पूछा गया है', मुसलमान हाशिए पर धकेला गया समुदाय है।' तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग कर कोई से दो तर्क रेखांकित करिए। उत्तर सुझाने के लिए सच्चर कमेटी की रपट को आधार बताया है, जिसमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है और उसे हिंदुओं से जानमाल का खतरा है।

नेपाल की अस्थिरता के लिए नेहरू जिम्मेदार : सुदर्शन

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक कुप्प.सी. सुदर्शन ने नेपाल की अस्थिरता के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया है। श्री सुदर्शन ने दावा किया कि वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही नेपाल ने भारतीय संघ में मिलने का प्रस्ताव पेश किया था लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने प्रस्ताव केवल इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का भय था। नागपुर में संघ कार्यकताओं के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर में संघ प्रमुख ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद ही तत्कालीन नेपाल नरेश मत्रुक प्रसाद कोईराला ने अपने देश को भारत में मिलाने की इच्छा से पंडित नेहरू को अवगत कराया था, लेकिन नेहरू ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसी का नतीजा है कि माओवादी चीन की शह पर नेपाल में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हुए। इसके साथ ही श्री सुदर्शन का यह भी आरोप है कि तिब्बत पर चीन का कब्जा भी पंडित नेहरू की ही देन है।

पाक में आतंकवादियों को मिलती है शरण

भारत अगर आतंकवाद के लिए पाकिस्तान का विरोध करता है तो मुस्लिम तुष्टिकरण के शिकार हमारे ही देश कुछ राजनीतिक दल इसे राजनीतिक द्वेष बताकर आतंकवाद को संरक्षण देते हैं, जबकि अफगानिस्तान ने भी आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की जमकर आलोचना की है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री रांगिन स्पांटा ने तो यहां तक कहा है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में शरण मिलती है, उन्होंने तालिबान समर्थक, आतंकवादियों से समझौता करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को अपने देश में खुली छूट दे रहा है। यहां यह जानना होगा कि पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान से सटी सीमा पर सक्रिय आतंकवादियों के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। विदेश मंत्री रांगिन स्पांटा का मानना है कि पाकिस्तान सरकार के फैसले से आतंकवादियों की ताकत बढ़ेगी और वे अफगान सीमा में और हमले करेंगे श्री स्पांटा ने तुष्टिकरण की नीति को ही गलत बताया है जो किसी भी देश की स्थिरता के लिए सीधा खतरा है।

परमाणु करार का इस वर्ष वक्त नहीं : एरकरमैन

भारत में राजनीतिक उथल पुथल का केन्द्र बना भारत – अमरीकी असैन्य परमाणु करार पर अमरीकी संसद को मुहर लगाने का समय इस वर्ष तो नहीं मिलेगा। प्रतिनिधि सभा की मध्यपूर्व और दक्षिण

आर्थिक विश्व

एशिया पर उप समिति के अध्यक्ष गैरी एकरमैन का तो यही मानना है। पाकिस्तान की यात्रा पर आए एकरमैन ने कहा है कि वे इसे समय पर और निश्चित तौर पर राष्ट्रपति बुश के कार्यकाल में पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा कैलेंडर वर्ष में हम इस पर काम नहीं कर सकेंगे।

विश्व माफियाओं की देन है खाद्य संकट

योजना आयोग के सदस्य प्रो. अभिजीत सेन की बात पर अगर विश्वास करें तो इस देश में खाद्य संकट विश्व माफियाओं की मिलीभगत का दुष्परिणाम है। उनका मानना है कि वास्तविक समस्या प्रबंधन की है न कि खाद्यान्न उत्पादन की। प्रो. सेन का दावा है कि अगर हमने ग्लोबल स्तर पर मिलकर काम नहीं किया तो अगले 20 से 30 वर्ष में पूरे विश्व के समक्ष निश्चित तौर पर खाद्य संकट खड़ा हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फाइनेंस के सीएमडी जयदेव अग्रवाल ने कहा है कि इंसान की जरूरतभर का खाना तो विश्व में उपलब्ध है, लेकिन लालच पूरा करने का भोजन नहीं है। प्रो. सेन का कहना है कि वायदा कारोबार करने वाले विश्व खाद्यान्न माफियाओं ने अपना शिकंजा कस लिया है और वे ही उपभोक्ता बाजार को नियंत्रित कर रहे हैं। डॉ. अग्रवाल ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की है कि वह विश्व में खाद्य पदार्थों के दामों पर नियंत्रण लगाने में कमजोर साबित हुआ है।

जैव ईधन की खेती से ही खाद्य संकट

विश्व बैंक की ताजा गोपनीय रिपोर्ट में खाद्य संकट के लिए मुख्य रूप से जैव ईंधन की खेती को ही जिम्मेदार माना गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ वर्षों में अमरीका और यूरोप ने बड़े पैमाने पर जैव ईधन की खेती को बढ़ावा दिया। इसके लिए किसानों को भरपूर सब्सिडी प्रदान की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान खाद्यान्न के उत्पादन को छोड़ नकदी फसल के रूप में जैव ईधन की खेती करने लगे। अमरीका ओर यूरोप मे गेहूं का उत्पादन लगभग 30 फीसदी गिर गया और इसकी कीमत एक साल में 80 फीसदी तक बढ़ गई। रहा सहा कसर आष्ट्रेलिया में आए भीषण सूखे ने पूरा कर दिया। पूरे विश्व में अचानक खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। अब संयुक्त राष्ट्रसंघ भी इस चिता में लगा है कि किसी भी तरह किसानों को फिर से खाद्यान्न उत्पादन की तरफ मोड़ा जाए ताकि दुनिया के लिए खाद्यसुरक्षा का सुनिश्चित की जा सके।

वामपंथियों की समर्थन वापसी के बाद

यूपीए में भगदड़

■ विक्रम उपाध्याय

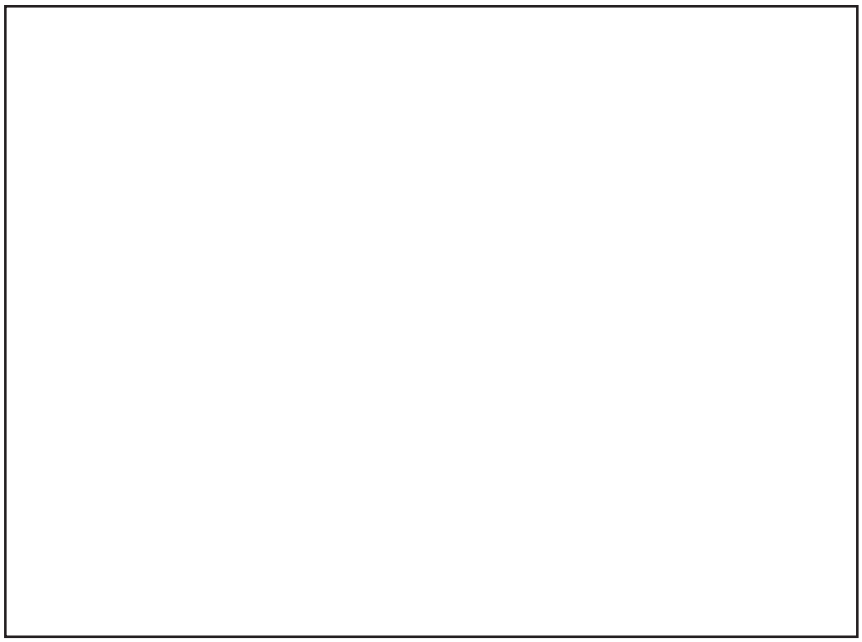

रास्ते अलग-अलग : प्रधानमंत्री मनमोहन सिह एवं माकपा नेता प्रकाश कारत

यह महज इत्तेफाक नहीं कि जिस दिन वामपंथियों ने मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कि उस दिन यानी 8 जुलाई को न तो प्रधानमंत्री दिल्ली में थे और न राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वामदलों ने जानबूझ कर यह दिन चुना ताकि समर्थन वापसी की औपचारिकता से पहले उसके प्रचार का भरपूर समय उन्हें मिल सके। अभी नहीं लगभग एक माह पहले ही कांग्रेस ने यह लगभग यह तय कर दिया था कि परमाणु करार के लिए वह हर हाल में आगे बढ़ेंगे। बल्कि बजट से पहले ही कांग्रेस ने यह मन बना लिया था कि वामदलों के दबाव में झुकने के बजाय कुछ नए समर्थन जुटा लिए जाए। इस साल 19 फरवरी को अगरतल्ला में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि वामदलों की नाइंसाफी वह बर्दाश्त नहीं करेगी। जब मनमोहन सिंह ने जब यह घोषणा कर दी कि अमरीका के साथ होने वाले करार को अमली जामा पहनाने के लिए व प्रस्ताव आईएईए में ले जाने के लिए कटिबद्ध है तो वामदलों ने सोनिया का दरवाजा खटखटाया पर सुनने में यह आया कि सोनिया ने 18 जून को ही वामपंथियों को स्पष्ट कर दिया कि वह प्रधानमंत्री को इस मामले में विचार बदलने के लिए नहीं कहेंगी। लेकिन इसके बावजूद वामपंथियों ने तब समर्थन वापसी का फैसला नहीं लिया। दरअसल पिछले दरवाजे से सत्ता का स्वाद चख रहे वामपंथियों में ही एक राय नहीं थी कि कब सरकार का मोह छोड़ा जाए। वेटरन माकपाई ज्योंति बसु तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सरकार से समर्थन वापस लिया जाए। उन्होंने इस मामले में सार्वजनिक बयान जारी कर प्रकाश कारत और सीताराम येचुरी को समझाने की कोशिश की।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की माने तो वामदलों को वास्तव में अमरीका के साथ परमाणु समझौते को लेकर तार्किक स्तर पर कोई आपत्ति नहीं थी,उनके लिए यह मसला वैचारिक और वोट बैंक से ज्यादा जुड़ा था। वह भी बंगाल और केरल में चुनाव निकट आते देख माकपा ने समर्थन वापसी का यह फैसला लिया। कांग्रेस के इस नेता ने यह सवाल किया कि यदि वास्तव में वामदलों को अमरीका के साथ किसी सामरिक समझौते पर आपत्ति होती तो वे कब के समर्थन वापस ले सकते थे। मनमोहन सिंह ने सामरिक मामले में अमरीका परस्त नीति का फैसला तो तभी कर लिया था जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार जुलाई 2005 में अमरीका दौरे पर राट्रपति ब्रु के साथ एक साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। उसके तुरंत बाद विदेशमंत्री प्रणव मुखर्जी भी अमरीका पहुंचे और उन्होंने बकायदा भारत-अमरीका सामरिक रक्षा समझौता के खाके पर हस्ताक्षर किया। उसी समझौते के बाद परमाणु समझौते की भूमिका तैयार हुई। वामपंथियो ने तब सिर्फ दिखावटी विरोध दिखाते हुए सरकार को समर्थन जारी रखा।

दरअसल वामपंथी मनमोहन सिंह सरकार के साथ अब तक इसलिए खड़े थे कि उन्हें यह आशा थी कि यदि उन्होंने सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाए रखा तो उत्तर भारत में भी उनकी राजनीतिक पकड़ बन सकती है और आने वाले दिनों में केंद्र

मायावती के सताये मुलायम सिहं और अमर सिहं की सोनिया गांधी से कब तक निभेगी यह कहना बहुत मुश्किल है।

सरकार में उनकी भूमिका और बढ़ सकती है। स्वयं प्रकाश कारत ने पिछले साल दिसंबर में यह बयान जारी किया था कि यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अमरीका के साथ प्रस्तावित परमाणु समझौते के प्रारूप को आईएईए में ले जा सकते हैं और देश हित के कुछ मसलों पर बात कर सकते हैं। उन्होंने तब यह खुल कर कहा था कि गुजरात चुनाव से पहले वह परमाणु मसले पर केंद्र की सरकार को अस्थिर करने की सोंच भी नहीं सकते, क्योंकि उससे भाजपा को फायदा होगा। जाहिर है वामदल अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए कांग्रेस को मोहरा बना रहे थे। इस मामले में पश्चिमबंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने खुले रूप में वामपंथियों के इरादे सामने रख दिए थे। उन्होंने यूपीए के गठन के समय कहा था- हम जानते हैं कि कांग्रेस परंपरागत रूप से जमींदारों की पार्टी है। उसका चरित्र गरीब विरोधी है, वामदलों से ाायद ही कहीं कांग्रेस की समानता है, लेकिन हम 'सांप्रदायिक शक्तियों को बाहर रखने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल 'हथियार' के रूप में करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस वामपंथी उत्तरभारत में अपना जनाधार कांग्रेस के बूते बढ़ाने में बुरी तरह विफल रहे। पंजाब, गुजरात,हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में भाजपा और सहयोगियों की सरकार बनाने से वामपंथी रोक नहीं सके। अब वे खिसियानी बिल्ली की भूमिका में हैं। उन्हें यह अहसास हो गया है कि राजनैतिक वैतरनी कांग्रेस की नाव में बैठ कर पार नहीं कर सकते। वामदलों में शामिल आरएसपी के नेता अबनी राय ने पिछले दिनों इकतरफा यह घोषणा कर दी थी कि उनकी पार्टी अब और यूपीए को समर्थन नहीं दे सकती, क्योंकि केंद्र सरकार को समर्थन देने की अब बड़ी कीमत वामपंथियों को चुकानी पड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस ने अब वामदलों के सुझाव मानने बंद कर दिए हैं, चाहे वह महंगाई रोकने के लिए जरूरी उपाय से संबंधित हो या फिर परमाणु समझौते से।

सच्चाई भी यही है। कांग्रेस ने धीरे-धीरे वामपंथियों को नीति निर्धारण से अलग कर दिया था। यूपीए और वामदलों के बीच बनी समन्वय समिति एक तरह से कार्यविहीन हो गई थी। वामपंथी चाहते थे कि महंगाई और विनिवेश के मुद्दे पर इस समन्वय समिति में चर्चा हो लेकिन कांग्रेस इस तरह की बैठकों से खुद की बचती आ रही थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रति के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के बाद इस समन्वय समिति की कोई गंभीर बैठक ही नहीं हुई। उसके बाद भी सरकार को समर्थन जारी रखने के कारण वामपंथियों की किरकिरी होने लगी थी, लोगों ने उन्हें सिर्फ 'भौंकने वाला कुत्ता' करार दिया था। वामपंथियों मं इस बात को लेकर बेचैनी होने लगी थी कि सांप्रदायिकता के नाम पर गरीब विरोधी सरकार को लगाताार समर्थन देने का कहीं उल्टा परिणाम न आ जाए।

केद्र से समर्थन वापस लेने के पीछे एक कारण और भी है कि केरल और बंगाल की वाम सरकारें तेजी से जनाधार खोती जा रही हैं। वामदलों को यह डर सता रहा था कि यदि अगले विधानसभा के चुनाव स्थानीय मुद्दे पर लड़े गए तो जनता जमीन को लेकर बंगाल में हुए खूनखराबे का हिसाब पूछेगी। खेतीहर जमीन उद्योगपतियों के हवाले करने का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग राजनीतिक बदले के लिए किया जाना एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इसलिए वामपंथी राष्ट्रीय मुद्दों को राजनीतिक पटल पर लाना चाहते हैं।अमरीका का डर दिखाकर मुस्लिम वोट को अपने पास खींचना चाहते हैं।

दुश्मन से दोस्त बनी सपा के लिए भी मुस्लिम वोट के बहुत मायने हैं। जो तर्क वामपंथियों के लिए सही बैठते हैं वहीं तक सपा के मुस्लिम नेता भी देंगे। अभी से ही सपा के मुस्लिम नेता कांग्रेस के साथ बने इस नए गठबंधन को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर करने लगे हैं। यह देखना कम दिलचस्प नहीं रहेगा कि मुस्लिम वोट पर बहुत हद तक उम्मीद टिकाए मुलायम सिंह लोकसभा चुनाव के दौरान उस कौम को क्या जवाब देंगे जो यह मानती है कि अमरीका के साथ दोस्ती कहीं न कहीं मुस्लमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा कर की जा रही है। उधर कांग्रेस के लिए भी मुलायम को ढोंना आसान नहीं होगा। यदि कांग्रेस अगली सरकार के लिए कोई उम्मीद पालती है तो वह उत्तरप्रदेश में अपनी सीटें सपा को देने के लिए कत्तई तैयार नहीं होगी।

महंगाई और कूटनीतिक कमज़ोरी है सरकार की उपलब्धि : गुरूमूर्ति

जाने माने चार्टेड एकाउटेंट और स्वदेशी जागरण मंच के वरिष्ठ नेता एस. गुरूमूर्ति का मानना है कि मनमोहन सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां महंगाई और कूटनीतिक मोर्चे पर विफलता है और कांग्रेस के राज मे देश ने अपना सम्मान खोया है। प्रस्तुत है उनसे बातचीत के प्रमुख अंश – सं.

वामपंथी दलों द्वारा समर्थन वापसी की घोषणा के बाद मनमोहन सिह की सरकार को क्या नैतिक रूप से सत्ता में बने रहना चाहिए या कांग्रेस को शीघ्र की चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए!

कांग्रेस से नैतिकता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वैसे वामपंथी भी नहीं चाहते कि वे तुरंत चुनाव मैदान में जाएं। मुझे तो लगता है कि समर्थन वापसी की घोषणा के बाद वामदल कुछ ऐसा करेंगे कि मनमोहन सिंह की यह सरकार चलती रहे। सरकार से समर्थन वापस लेने के पीछे उनका उद्देश्य परमाणु मसले पर फैसला लेने से सरकार को रोकना नहीं है। दरअसल, वह अपने निजी कारणों से समर्थन वापस ले रहे हैं। एक तो वे केरल और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हो सकते। दूसरे कुछ अन्य दलों की तरह वामपंथियों ने भी मान लिया है कि परमाणु मसले पर सरकार के साथ खड़े होने से मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिन जाएगा। माकपा की भी यही सोच है कि पूरी दुनिया के मुसलमान अमरीका के खिलाफ हैं और भारत का अमरीका के साथ परमाणु समझौता होने से मुस्लिम समुदाय को बहुत सदमा पहुंचेगा। वैसे भी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 28 फीसदी है और केरल में भी मुसलमानों की संख्या काफी अधिक है।

लेकिन वामदल तो प्रस्तावित परमाणु समझौते में शामिल 1,2,3 मसौदे को देश के खिलाफ मानते हैं और इसी को समर्थन वापसी का कारण बता रहे हैं!

कहां बात कर रहे हैं। वामपंथियों की डिक्शनरी में राष्ट्रहित जैसा कोई शब्द नहीं होता। वैचारिक रूप से वे देश के साथ नहीं अपने आंदोलन के साथ जुड़े हैं। नेपाल में माओवादियों की सरकार का गठन उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि भारत में माओवादियों की हिंसा का रूकना। वे भारत से ज्यादा चीन की उपलब्धियों से खुश होते हैं।

उपलब्धियों की बात करें तो क्या मनमोहन सिंह की सरकार की कोई विषेश उपलब्धि आपको दिखाई देती है!

उपलब्धियों की बात क्या करें, मनमोहन सिंह की सरकार के चार साल के काम काज के दौरान कूटनीतिक रूप से, सैनिक रूप से और राजनीतिक रूप से भारत का सम्मान पूरी दुनिया में कम हुआ है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते दुनिया के देशों ने सरकार के फैसले को गंभीरता ने नहीं लिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह माना गया कि मनमोहन सिह के फैसले के कोई मायने नहीं हैं। 2004 में भारत की

जबर्दस्त धाक थी। पाकिस्तान हमसे डरने लगा था। अफगानिस्तान में हमारी उपस्थिति बहुत मजबूत थी। दुनिया यह मानने लगी थी कि भारत सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक बड़ा देश है। आज पाकिस्तान हमारे सर पर चढ़कर बोल रहा है, अमरीका हम पर भारी दबाव बना रहा है। यह सब इसलिए हुआ कि सप्रंग सरकार की कमान प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं बल्कि सोनिया गांधी के हाथ में रही।

आर्थिक मोर्चे पर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं!

महंगाई और खाद्यान्न संकट मनमोहन सिंह सरकार की देन है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार आर्थिक मोर्चे पर किस कदर खरी उतरी है। यह कहना महज बहाना बनाना है कि अंतरराष्ट्रीय कारकों ने देश में महंगाई बढ़ाई है। दरअसल सरकार की लापरवाही और कुप्रबंधन इस स्थिति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। मैं एक उदाहरण देता हूं। वर्श 2002 में देश में अनाज उत्पादन मे अचानक गिरावट आई । उस वर्ष हमारा अनाज उत्पादन 2010 लाख टन से गिरकर महज 1740 लाख टन रह गया, लेकिन फिर भी महंगाई नहीं बढ़ी, कारण कि सरकार के स्टॉक में खाद्यान्न भरे पड़े थे। उत्पादन कम होने के बाद भी किसी जमाखोर की यह हिम्मत नहीं हुई कि वह कृत्रिम रूप से खाद्यान्न का संकट पैदा कर दे। जमाखोरों को यह मालूम था कि सरकार खुले बाजार में भरपूर खाद्यान्न भेज देगी। लेकिन 2006–07 में स्थिति बदल गई। सरकार के गोदामों में अनाज मांग के मुकाबले 10–15 फीसदी भी नहीं था। जमोखोरों ने इसका भरपूर फायदा उठाया नतीजा यह हुआ कि आम आदमी को खाने की कीमत उसकी अपनी औकात से ज्यादा चुकानी पड़ रही है।

लेकिन सरकार ने हाल ही में रबी की भरपूर खरीददारी की है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है!

यह सही है कि सरकार ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। लेकिन सवाल यह उत्पन्न होता है कि कितने प्रतिशत किसानों को इससे फायदा हुआ है। ने शनल सैंपल सर्वे ने हाल ही में यह बताया है कि देश के सिर्फ सात फीसदी किसान ही जानते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। उनमें से भी 90 फीसदी किसान यह नहीं जानते कि इस समर्थन मूल्य का लाभ कैसे उठाए। अपने पैदावार की ग्रेडिंग कैसे करे। यदि सरकार समर्थन मूल्य के बारे में किसानों को जागरूक करे तो किसानों को उनकी मेहनत की अच्छी कीमत मिल जाए और उपभोक्ता को उचित मूल्य पर खाद्यान्न।

रूपये में एक फीसदी अवमूल्यन का मतलब है तेल आयात बिल पर 80 पैसे का अतिरिक्त बोझ पड़ना। यानी इस हिसाब से कच्चे तेल की खरीद में लगभग छह रूपये 40 पैसे की बढ़ोतरी हो

सरकार यह कह रही है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण ही मुद्रा स्फीति की दर लगातार बढ़ रही है!

सरकार गलत तर्क दे रही है। जनवरी से ही लगातार महंगाई बढ़ रही है। जिस समय वित्तमंत्री बजट प्रस्तुत कर रहे थे उस समय भी मुद्रा स्फीति की प्रवृति बढ़ने की ओर थी। महंगाई पर तेल की कीमत का असर तो जून में होना चाहिए था न कि जब केंद्र ने पेट्रोल के दाम में पांच रूपये और डीजल के दाम में तीन रूपये की बढ़ोतरी की थी। उसके पहले तो तेल के दाम नहीं बढ़े थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी का यह असर हम पर कम पड़ता यदि रिजर्व बैंक ने सही फैसला लिया होता। आप सबको मालूम है कि पिछले दो वर्ष में डॉलर के मुकाबले रूपये की कीमत लगातार बढ़ती रही। लेकिन आरबीआई ने वर्ष 2007–08 में अचानक डॉलर की भारी खरीद कर उसे मजबूती प्रदान कर दी। देश में लगातार विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने के बावजूद आरबीआई ने इस वर्ष 78 अरब डॉलर खरीदे। यही नहीं फारवर्ड बाजार से भी ने इस केंदीय बैंक ने 16 अरब डॉलर का सौदा कर डाला। आरबीआई के इस कदम से दुनिया भर में मार खा रहा डॉलर मजबूत हो गया और रूपये का लगभग आठ फीसदी अवमूल्यन हो गया। हमें यह मालूम होना चाहिए कि रूपये में एक फीसदी अवमूल्यन का मतलब है तेल आयात बिल पर 80 पैसे का अतिरिक्त बोझ पड़ना। यानी इस हिसाब से कच्चे तेल की खरीद में लगभग छह रूपये 40 पैसे की बढ़ोतरी हो गयी। जहां तक खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय परिस्थतियों को जिम्मेदार बताने की बात है तो मैं यही कहूंगा कि इस समय हमने आयात लगभग रोक दिया है यदि सही नीति होती तो अनाज की कीमत कम होनी चाहिए थी लेकिन दाम कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

सीपीआई महासचिव ए बी बर्धन का एलान

महंगाई और करार पर घेरेंगे सरकार

परमाणु करार के मसले पर आखिरकार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लेफ्ट की मांग अनदेखा कर उन्हें ठेंगा दिखाया तो लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया। लेकिन देश में महंगाई जैसे अहम मसलों के बीच लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया परमाणु डील के मसले पर। क्या महंगाई कोई मसला नहीं है और अब लेफ्ट की क्या रणनीति है–इस पर सीपीआई के महासचिव ए बी बर्धन से बात की आशुतोष ने।

क्या आप संसद में सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे।

निश्चित रुप से करेंगे। हमने तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील से कहा है कि मनमोहन सिंह को सदन में विश्वास मत हासिल करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है।

महंगाई आसामान छू रही है, और आप परमाणु करार पर रार मचाते रहे।

देखिए महंगाई का मसला हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि ये सीधे तौर पर जनता के जीवन को प्रभावित करता है। मनमोहन सरकार मुद्रास्फीती से निपटने में बुरी तरह विफल रही है। रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने से जनता की कमर टूट रही है। इन सारी स्थितियों का ताल्लुक यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों से है। लेकिन परमाणु करार का विरोध इसलिए भी जरुरी है कि सरकार परमाणु ऊर्जा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है और जनता में गलतफहमियां फैलायी जा रही हैं। भारत की विदेश नीति को अमेरिका संचालित करे – ये हमें कतई स्वीकार नहीं। इसलिए हमनें एटमी डील के साथ साथ यूपीए सरकार की जनविरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने का ऐलान किया है।

क्या महंगाई कोई मसला नहीं है।

हम तो कह ही रहे हैं कि महंगाई बहुत बड़ा मसला है। चारों वामपंथी दलों की तरफ से सरकार को मुद्रास्फीती कम करने के सुझाव दिए गए थे। लेकिन अहम मसले को छोड़कर मनमोहन सरकार का सारा ध्यान अमेरिका से किए गए वायदे को पूरा करने में लगा रहा। ये दुर्भाग्य पूर्ण रहा। अब जनता के बीच सरकार की करार को पूरा करने की जिद और बढ़ती महंगाई दोनों को मुद्दा बनाकर चारों लेफ्ट पार्टियां 16 जुलाई से देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे।

यूपीए सरकार के दौरान महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़े लेकिन लेफ्ट पार्टियां चुपचाप तमाशा देखती रहीं।

ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे रहे। महंगाई कम करने के उपायों का दस्तावेज हमने यूपीए को बहुत पहले ही दे दिया था। लेकिन सरकार ने उस पर अमल नहीं किया। इसके अलावा लेफ्ट ने समय समय पर जनांदोलनों के जरिए महंगाई के मुद्दे पर यूपीए सरकार की आंखें खोलने की कोशिश भी की। लेकिन सरकार का सारा ध्यान परमाणु करार पर लगा रहा। और आप देख रहे हैं कि इसके लिए उन्होंने हर किस्म की जोड़तोड़ की है।

तेल की कीमतें आसमान छू गईं। महंगाई से गरीब के घर का बजट बिगड़ गया लेकिन सर्वहारा की पैरोकार लेफ्ट पार्टियों ने सरकार का साथ दिया–सिवाय परमाणु करार के मसले को छोड़कर। क्यों?

हम सरकार के साथ कभी थे ही नहीं। हमने सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। वो भी सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकने के लिए। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि हम सरकार के हर फैसले में साथ देते रहे। हमनें पिछले साढे चार साल में जब भी यूपीए सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम से भटकी उनके साथ मिल बैठकर मश्विरा दिया और कई मौकों पर सरकार को अपने फैसले बदलने पर मजबूर किया। ये लेफ्ट ही था, जिसके विरोध के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकार ने उतनी नहीं बढ़ायीं, जितनी वो बढ़ाना चाहती थी।

क्या अगले चुनावों में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होगी, और इससे न निपटने का खामियाजा यूपीए को भुगतना होगा?

यूपीए रहेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता। इसलिए ये सवाल बेमानी है। हां, इतना जरुर है कि महंगाई के मसले पर ध्यान न देने का खामियाजा यूपीए सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखा जाए तो ये जनाक्रोश ही है कि यूपीए सरकार के गठन से लेकर अब तक हुए 12 विधानसभा चुनाव में यूपीए की पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा है। लेफ्ट सरकार को कई बार चेताता रहा कि महंगाई के मुद्दे को अनदेखा नहीं किया जाए। पर सरकार ने एक नहीं सुनी।

क्या गंगा लुप्त हो जायेगी?

■ **निरंकार सिंह**

गंगा और यमुना कोई साधारण नदियां नहीं हैं। सदियों से नदियां हिंदुओं की आस्था का केंद्र रही हैं। परन्तु आज नदियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। यदि हम गंगा के धार्मिक महत्त्व को छोड़ भी दें, तब भी गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक इसके किनारे बसी हुई तीस करोड़ से अधिक आबादी और तमाम जीव – जंतुओं, वनस्पतियों के जीवन का मूल आधार गंगा ही है। गंगा के बिना गंगा की घाटी में जीवन संभव नहीं है, इसलिए इसकी रक्षा, इसे निर्मल बनाये रखने की चिंता और प्रयास जो नहीं करता है वह अपने साथ ही आत्मघात कर रहा है। वेदों से लेकर वेदव्यास तक, वाल्मीकि से लेकर आधुनिक कवियों और साहित्यकारों ने इसका गुणगान किया है। इसका भौगोलिक, पौराणिक, एतिहासिक, सांस्कृतिक और साथ–साथ अध्यात्मिक महत्त्व है। परन्तु गंगा और यमुना जैसी पावन नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त कराने की चिंता अब शायद सरकार को नहीं हैं, इसीलिए नदियों को बचाने के लिए अदालतों को बार–बार पहल करनी पड़ती है। सरकार यदि इन पावन नदियों की साफ–सफाई भी नहीं कर सकती है, तो फिर उसके होने न होने से क्या औचित्य है? जब तक योजनाओं और घोषणाओं को पूरी इच्छा शक्ति से लागू नहीं किया जायेगा और लोगों को जागरूक नहीं किया जायेगा, तब तक हम गंगा–यमुना जैसी जीवनदायी नदियों को नहीं बचा सकते हैं। कुछ पर्यावरण वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि यही हाल रहा तो अगले चार–पांच दशकों में गंगा भी सरस्वती की तरह लुप्त हो जाएगी।

गंगा को शास्त्रों ने एक स्थावर, सुगम नित्य तीर्थ कहा है। वेदों और पुराणों में गंगा को बारंबार तीर्थमयी कहा गया है।

स्वदेशी जागरण मंच ने निकाली गंगा बचाओ रैली

विकास के नाम पर विनाशकारी है बांध : डॉ. अश्विनी महाजन

गंगा बचाओ आंदोलन के समर्थन में स्वदेशी जागरण मंच ने गंगा बचाओ रैली निकालकर गंगा भक्तों का आह्वान किया कि वे भारत की संस्कृति एवं करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी गंगा मां का अस्तित्व बचाए रखने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार रहें। स्वदेशी जागरण मंच की रैली में शामिल हुए सैकड़ों गंगा भक्तों ने यह संकल्प लिया कि वे मंदिर, मस्जिद, गुरूदारा एवं घर–घर जाकर गंगा बचाओ आंदोलन को जन–जन का आंदोलन बनाकर गंगा मैया का अस्तिव मिटाने वालों की साजिश को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे।

22 जून रविवार को स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर आजादपुर में इंद्रानगर के महावीर मंदिर से आदर्श नगर तक गंगा बचाओ रैली निकाली गई। रैली में पांच सौ से अधिक स्कूटर–मोटरसाइकिलें व सैकड़ों पैदल यात्री शामिल

महाभारत में उल्लेख है कि गंगा अपना नाम उच्चारण करने वाले के पापों का नाश करती है, दर्शन करने वाले का कल्याण करती है तथा स्नान–पान करने वाले की सात पीढ़ियां तक पवित्र करती है। यह वारि–प्रवाह आकाश से पृथ्वी पर यूं ही नहीं आया, इसके लिए भागीरथ ने बहुत तप किया था। भगीरथ की जिस गंगा में कभी निर्मल जल की धारा बहती थी, आज वहां सड़ांध और दुर्गन्ध के भभके उठते रहते हैं। कानपुर में तो इस नदी ने एक तरह से नाले का रूप ले लिया है और यहां वह अपने स्थान से भी खिसक रही है। नदियों को प्रदूषण से बचाना हमारा कर्तव्य है लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करने के बजाय हम गंगा के प्रवाह को मोड़ने या उस पर बांध बनाये जाने को लेकर बेमतलब हो–हल्ला मचाते हैं। जरूरत इस बात की है कि गंगा को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए।

गंगा कोई साधारण नदी नहीं है, वह इस धरती पर सतत् प्रवाहमयी चैतन्य की धारा है। गंगा की उत्पत्ति के अनुसार इसके कई नाम हैं। यह विष्णु के चरण से निकली है इसलिए विष्णुपदी, भागीरथ की तपस्या से उतरी है, इसलिए भागीरथी, जाह्नू की कृपा से मुक्त हुई, इसलिए जाह्नवी और पृथ्वी पर उतरी है इसलिए गंगा कहलाती है। वह इस पृथ्वी पर पत्नी तथा माता के रूप में प्रसिद्ध है। वह शान्तनु की पत्नी और भीष्म की माता भी हैं। पुराणों में गंगा को लोकमाता कहा गया है। भगवत्स्वरूपिणी गंगा का पूजन, कीर्तन और चिन्तन करना और भगवान का पूजन करना एक समान माना गया है। नाना प्रकार की औषधियों एवं स्वाथ्यवर्द्धक अमृतोपम गुणों से सम्बन्धित इसके जल में स्नान कर प्रसन्नता, तृप्ति, शक्ति–वर्द्धन और स्वास्थ्य के तत्वों को अनायास ही जीव प्राप्त करता रहता है। गंगा में अवगाहन से अंतःकरण भी प्रफुल्लित हो जाता है और उसमें देवी चेतना का संचार होने लगता है। इसलिए कोटि–कोटि भारतीयों के लिए गंगा माता है, धरित्री के समान पोषक और अपकर्मों से ऊपर उठाने वाली, धर्म की भांति तत्वधारक तथा परमेश्वर की भांति कैवल्य एवं मोक्ष प्रदाता है।

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है. ..''स्त्रोतसामस्मि जाह्नवी'' अर्थात नदियों में, मैं जाह्नवी (गंगा) हूं। भगवान् श्री कृष्ण के इस कथन से गंगा और भगवान में कोई भेद नहीं है। ब्रह्म सिद्धान्त के अनुसार गंगा की धारा और जगत के प्रवाह में कोई विशेष अन्तर नहीं है। वास्तव में विश्व की विभिन्न रूप–रचनाओं में जो सारस्वत एवं सर्वनिष्ठ सत्ता निवास करती है, उसी ''एक'' की गति चेतना को गंगा कहा जाता है – जगत्प्रवाहे बहुरूपभिन्नं यदेकरूपं भवतीह गंगा। भारतीयों के हृदय में गंगा के प्रति इतनी श्रद्धा है कि वे सभी नदियों में गंगा का ही दर्शन करते हैं। जैसे तुलसी की घोषणा है कि जगत् के सभी नर–नारी सियाराम मय हैं वैसे ही मार्कण्डेय पुराण का कहना है कि ''सवा गंगाः समुद्रगाः'' अर्थात समुद्र से मिलने वाली सारी नदियां गंगा का ही रूपान्तर हैं। वैसे भी जल को जीवन का वायु के बाद दूसरा सबसे बड़ा आधार माना गया है। जल जीवन का पर्याय है, अतः समस्त जीवन–धारा को प्रतीकात्मक रूप से गंगा–प्रवाह कहा जाता है।

दुनिया की किसी भी नदी ने गंगा की भांति न तो मानवता को प्रभावित किया है और नहीं भौतिक सभ्यता तथा सामाजिक नैतिकता पर इतना प्रभाव डाला है। जितने व्यक्तियों और जितने क्षेत्रों को गंगा के जल से लाभ मिलता है, उतना संसार की

हुए। रैली के दौरान सभी गंगा भक्त इस क्षेत्र के प्रत्येक मंदिर, गुरूद्वारा और मस्जिद में गए जहां गंगा भक्तों का बड़ी ही आत्मीयता के साथ स्वागत हुआ और आश्वासन मिला कि गंगा आंदोलन की अलख जगाए रखने के लिए उन्हें सब प्रकार का सहयोग मिलेगा। महावीर मंदिर से शुरू हुई रैली आजादपुर, सरायपीपल थला, महेन्द्र पार्क, केशव पार्क, मजलिस पार्क, गोयल पार्क से घूमती हुई सनातन धर्म मंदिर पंचवटी आजादपुर में आकर संपन्न हुई।

रैली का नेतृत्व स्वदेशी जागरण मंच के उत्तरी क्षेत्र के संयोजक डॉ. अश्विनी महाजन ने किया। इनके साथ जितेन्द्र महाजन, राजकुमार भाटिया, अशोक जी, रमेश चंद तथा क्षेत्र की निगम पार्षद नीलम बुद्धिराजा सहित क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए। गंगा भक्तों की इस रैली का नेतृत्व कर रहे डॉ. अश्विनी महाजन ने नारा दिया कि ''घर–घर हमको जाना है, गंगा मां को बचाना है।'' 'हर–हर गंगे' और 'बंदेमातरम' के उद्घोष से शुरू हुई गंगा बचाओ रैली संबोधित करते हुए डॉ. अश्विनी महाजन ने कहा कि विकास के नाम पर बांध का निर्माण विनाशकारी है। बांध बनाकर अविरल धारा को रोकने का कुत्सित प्रयास है। उन्होंने एलान किया कि बांध बनाकर बिजली के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा।

श्री महाजन ने बताया कि गंगा मां के प्रति जहां लोगों की आस्था है वहीं इसका वैज्ञानिक प्रभाव भी है, इसके प्रति लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुरंग बनाकर गंगा की अविरल धारा को रोकने की कोशिश देश के प्रहरी हिमालय को भी नष्ट करने का प्रयास है। आर्थिक रूप से गंगा के योगदान का उल्लेख करते हुए डॉ. अश्विनी महाजन ने बताया कि नदियों के माध्यम से खाद के रूप में लाखों टन उर्वरा शक्ति भारत की भूमि को उपजाऊ

किसी और नदी से नहीं पहुंचता है। यह वस्तुतः भारतीय संस्कृति का मेरूदण्ड बन गयी है। गंगा के प्रवाह के चढ़ाव–उतार ने अनेक साम्राज्यों के चढ़ाव–उतार को देखा है। हस्तिनापुर, कान्यकुब्ज, पाटलिपुत्र, काशी, चम्पा आदि इस तट पर बसे थे। भारत में जल व्यापार और नव–शक्ति का प्रारम्भ गंगा की धाराओं से हुआ था। लगभग चार लाख वर्गमील की भूमि इसके पानी से सींची और उर्वर बनायी जाती है। भारत की एक तिहाई आबादी इसी के तट पर बसती है। इसकी महिमा फाह्यिान्, ह्वेनसांग, इत्सिंग आदि विदेशियों ने और रसखान, रहीम, ताज मीर, आदि मुसलमान कवियों ने भी गायी है। इन सारी बातों को छोड़ भी दें तो भी इसके अमृत के समान जल के कारण यह नदी भारत की जीवनदात्री है। सवा दो हजार वर्ष पूर्व महर्षि चरक ने कहा था कि ''हिमवत्प्रभवाः पथ्याः पुण्या देवर्षिसेविता'' हिमालय से निकलने वाला जल पथ्य है। ऋषियों ने इसका सेवन कर प्रमाणित कर दिया है।

वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी यह सिद्ध हो गया है कि दुनिया की नदियों में गंगा ही सबसे पवित्रतम नदी है। इसके जल में कीटाणुओं के उन्मूलन की क्षमता सबसे अधिक है। शरीर के विभिन्न अंगों के रोग इसके पवित्र जल से दूर हो जाते हैं। शुद्ध गंगाजल इस धरती पर एक दुर्लभ द्रव्य है। कुछ वर्ष पूर्व यूनेस्को के एक वैज्ञानिक दल ने हरिद्वार के निकट गंगा के पानी के अध्ययन के पश्चात कहा था कि जिस स्थान में पानी की धारा में मुर्दे, हड्डियां आदि दूषित वस्तुएं बह रही थीं वहीं कुछ फुट नीचे का जल पूर्ण शुद्ध था। अनुसंधानों से यह पता चला कि गंगा के जल में हैजे के कीटाणु तीन चार घण्टे में स्वतः मर जाते हैं। इसके जल की पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इसके तट पर मानव–वास नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार गंगा तट को मल–मूत्र–थूक आदि से दूषित करने वाला व्यक्ति पातकी होता है। अपनी नदियों और जल–स्रोतों को साफ सुथरा रखने का कर्तव्य हर व्यक्ति का होना ही चाहिए। क्योंकि हवा के बाद पानी ही हमारे जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।

वैश्वीकरण की नीतियों को लागू किये जाने के बाद से भारत दुनिया के विकसित देशों का कूड़ाघर बनता जा रहा है। एक तरफ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपना कचरा यहां की नदियों में बहा रही हैं तो दूसरी तरफ भारत में विकसित देशों ने अपने औद्योगिक अपशिष्ट को बेचने की जो प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से अपना रखी थी, उस पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने जनहित में फैसला देते हुए 1997 में पूरी तरह रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं, किन अज्ञात संधियों और कूटनयिक समझौतों के अन्तर्गत यह अत्यंत विषैला कचरा लगातार अलग–अलग माध्यमों से भारत में निरंतर आता रहा है। उच्चतम न्यायालय की रोक के बावजूद यह सिलसिला जारी है। भारी मात्रा में शीशे के अलावा परमाणु रियेक्टरों तथा परमाणु बमों में नियंत्रक तत्व के रूप में प्रयोग की जाने वाली कैड्मियम धातु भी गंगाजल में बड़ी मात्रा में पायी जा रही है। लेकिन इसकी सफाई के लिए चलायी जा रही योजनाओं का अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। इस चुनौती का मुकाबला किये बिना हमारा उद्धार गंगा नहीं कर सकती है। ❖

बनाती है। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच केन्द्र सरकार से यह मांग करता है कि वह पवित्र नदियों के प्रवाह को रोकने का प्रयास न करे और बांधों के निर्माण को ध्वस्त करे।

डॉ. महाजन ने इस बात पर भी जोर दिया कि वैज्ञानिक आधार पर भी यह सिद्ध हो चुका है कि बांध का निर्माण विनाशकारी है। इस देश में बाढ़ विध्वंसकारी बांधों का ही नतीजा है। केवल बिजली के लिए देश के भौगोलिक अस्तित्व को खतरे में डाल दिया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है।

क्षेत्र की निगम पार्षद एवं मलेरिया निरोधक समिति दिल्ली की उपाध्यक्ष श्रीमती नीलम बुद्धिराजा ने गंगा भक्तों को संकल्प दिलाया कि गंगा की कीमत पर सरकार से कोई समझौता नहीं करेंगे इसलिए इस आंदोलन को जन–जन तक पहुंचाना है ताकि सरकार बांध बनाने की योजना को रोकने के लिए मजबूर हो जाए। श्रीमती बुद्धिराजा ने कहा कि गंगा का महत्व किसी धर्म–जाति विशेष के लोगों के लिए ही नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लोग गंगा में स्नान करते हैं, उसे देवी मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गंगा मैया भी धर्म और जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती बल्कि जो भी श्रद्धाभाव से इसमें स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं।

स्वदेशी जागरण मंच के विशेष प्रतिनिधि व दिल्ली व्यापार प्रकोष्ठ भाजपा के मंत्री राजकुमार भाटिया ने रैली में आए युवकों का विशेष आभार व्यक्त करते हुए उन्हें संकल्प दिलाया कि पर्यावरणविद डॉ. गुरूदास अग्रवाल के संकल्प को व्यर्थ नहीं जाने देंगे बल्कि इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी करनी पड़ जाए पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि गंगा प्रत्येक भारतीय के रोम–रोम में बसी है, गंगा मोक्षदायिनी है, गंगा में एक बार स्नान करने से पापियों के पाप भी धुल जाते हैं, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि गंगा मां के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश न करें, उसकी जल धारा को अविरल बहने दिया जाए। ❖

प्राणों की बाजी लगाकर भी गंगा को बचाएंगे : डॉ. जी.डी. अग्रवाल

■ स्वदेशी संवाद

प्राणों की कीमत पर गंगा बचाने का संकल्प लेकर आमरण अनशन पर बैठे प्रख्यात पर्यावरणविद डॉ. गुरूदास अग्रवाल का कहना है कि भागीरथी (गंगा) भौतिकता का सामान नहीं है, जिसे मनुष्य चाहे जिस रूप में प्रयोग करे। गंगा भारतवासियों के लिए मां है। वह मां, जो लोगों के सारे पापों को धोकर खुद में समाहित कर लेती है। गंगा का जल हमारे लिए सामान्य जल नहीं है, जिसका प्रयोग हम केवल नहाने, पीने, सिंचाई सहित बिजली बनाने के लिए करते हैं बल्कि गंगा जल तो हमारी आत्मा को मुक्ति दिलाने वाला दैविक द्रव्य है। गंगा की रक्षा करना प्रत्येक हिंदुस्तानी का नैतिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी है। गंगा भक्त श्री जी.डी. अग्रवाल तो यहां तक निश्चय कर चुके हैं कि यदि मोक्षदायिनी भागीरथी गंगा को बचाने में उनकी जान भी चली जाए तो उन्हें इसका मलाल नहीं होगा बल्कि वो अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे।

उत्तरकाशी से आकर रोहिणी दिल्ली में आमरण अनशन पर बैठे डॉ. अग्रवाल इससे आहत हैं कि उद्गम स्थल उत्तरकाशी में ही गंगा की उपेक्षा की जा रही है। गंगा के मुख्य मार्ग पर सरकार द्वारा बांधों के निर्माण की योजना से गंगा का मूल स्वरूप ही खत्म हो गया है। यदि यही स्थिति बनी रही तो एक समय वह आएगा जब लोग पाप धोने के लिए स्वर्ग से आई गंगा व उसे लाने वाले भागीरथ को ही भूल जाएंगे और गंगा केवल एक धरोहर बनकर रह जाएगी। आने वाली पीढ़ियां भविष्य में गंगा को सिर्फ नाम से जानेंगी।

ज्ञातव्य है कि उत्तराखंड स्थित गंगा के उद्गम स्थल पर सरकार द्वारा दर्जनों बांध बनाने की योजना है। उत्तरकाशी के समीप मानेरीवेली पर दो बांध बनाए भी जा चुके हैं, और दोनों बांधों के बीच गंगा का पानी सुरंग के माध्यम से निकालकर उसकी अविरल धारा को रोक दिया गया है, जिस कारण वहां गंगा पूरी तरह से सूख गई है।

गंगा की मुक्ति के लिए विगत 13 जून से आमरण अनशन पर बैठने वाले डॉ. गुरुदयाल अग्रवाल आई आई टी कानपुर में इंजीनीयरिंग विभाग के पूर्व एचओडी एवं वर्तमान में चित्रकूट ग्रामोदय

गंगा बचाने के लिए यज्ञ

गंगा बचाने के लिए प्राणों की आहुति देने को तैयार प्रो. गुरूदास अग्रवाल के समर्थन में राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन भी खुलकर मैदान में आया है। सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए गंगा बचाओ यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के दौरान राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के प्रमुख एवं संयोजक श्री के. एन. गोविन्दाचार्य ने कहा कि गंगा मैया आज खतरे में है। केवल बिजली के लिए गंगा के 25 सौ किलोमीटर के प्रवाह मार्ग में जगह–जगह बांध बनाकर इसकी अविरल धारा को रोका गया है। श्री गोविन्दाचार्य का आरोप है कि गंगा के प्रवाह और गति को अनदेखा करते हुए पानी को मुख्य धारा से निकालने पर बेतहाशा खर्च किया गया है, जिस कारण उसकी स्वाभाविक गति धीमी हो गयी है। पर्यावरणविद डॉ. जी.डी. अग्रवाल के आमरण अनशन का पुरजोर समर्थन करते हुए गोविंदाचार्य ने गंगा भक्तों का आह्वान किया कि मौजूदा परिस्थितियों में गंगा को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। श्री गोविंदाचार्य के नेतृत्व में आयोजित गंगा बचाओ यज्ञ में आहुति डालने के समय गंगा मुक्ति आंदोलन से जुड़े सैकड़ों गंगा भक्तों ने सरकार से मांग की है कि गंगा को चौमुख से उत्तरकाशी तक नैसर्गिक रूप में बहने दिया जाए। इस मौके पर सरकार को यह भी चेतावनी दी गई कि अगर उसने गंगा मुक्ति का प्रयास समय रहते नहीं किया तो गंगा भक्त एकजुट होकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाएंगे।

विश्वविद्यालय के अवैतनिक प्रोफेसर हैं। डॉ. अग्रवाल ने स्वदेशी पत्रिका को बताया कि लगभग 30 वर्ष बाद जब वे वर्ष 2007 में उत्तरकाशी आए तो यह देखकर हैरान हुए कि पहले जो गंगा स्वछंद रूप से प्रवाहित हो रही थी, अब बांध निर्माण के कारण उसका नामोनिशान ही मिट चुका है। डॉ. अग्रवाल के वहां आमरण अनशन पर बैठने के बाद राज्य सरकार ने तो भैरन घाटी एवं पाला मैनेरी बांध परियोजना को रोक दिया है जबकि लौहारीनाग पाला परियोजना केन्द्र सरकार के अधीन होने से उसे नहीं रोका गया। राज्य सरकार के खिलाफ अनशन को तोड़कर डॉ. अग्रवाल 23 जून रोहिणी में केशवपुरम के महाराजा प्रताप भवन में अनशन पर बैठकर प्राण त्यागने का निश्चय कर चुके थे। हालांकि गंगा भक्तों के विशेष आग्रह पर उन्होंने एक शर्त पर अनशन तोड़ दिया कि जब तक सरकार बांध बनाने का कार्य नहीं रोकती वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। डॉ. अग्रवाल को भारी जनसमर्थन मिल रहा है, अब देखना यह कि केन्द्र सरकार अपनी जिद को छोड़ती है अथवा भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए डॉ. अग्रवाल का नाम भी उन शहीदों में लिखा जाएगा जो देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो गये। ❖

गंगा मां भारत की आत्मा है : अशोक सिंहल

विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंहल ने गंगा मैया को भारत की आत्मा बताया है और यह ऐलान किया कि अगर सरकारों ने गंगा के अस्तित्व को बचाने के प्रयास नहीं किए तो विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में ऐसा उग्र आंदोलन चलाएगी, जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साधु–संतों के आदेश पर पहले भी विश्व हिन्दू परिषद ने गंगा मां के लिए आंदोलन चलाए हैं। विहिप नेता ने केन्द्र सरकार को समझाने का प्रयास भी किया कि गंगा के प्रति भारतीय जनमानस की आस्थाओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। उन्होंने कहा कि भागीरथी का अस्तित्व मिटाने का षडयंत्र ठीक नहीं है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की सरकारें गंगा को सामान्य नदी और जल को सामान्य जल मानकर चलती हैं। सरकारों की इसी नीति का दुष्परिणाम है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी भागीरथी नदी पर परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। अशोक सिंहल ने सरकार को चेताया कि देशवासियों को ऐसा विकास नहीं चाहिए जो आस्थाओं के बलिदान पर किया जाए। जो विकास सांस्कृतिक जड़ों को ही खत्म कर दे, वह तो विष है।

गंगा भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार है : तोगड़िया

विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण भाई तोगड़िया ने गंगा को भारतीय संस्कृति का प्रमुख आधार बताते हुए कहा है कि हिन्दू समाज गंगा की अविरल धारा को बचाए रखने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी सूरत में गंगा पर बांध नहीं बनने दिये जाएंगे। श्री तोगड़िया ने कहा कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस गंगा को हिंदू जनमानस अपनी मां समझकर पूजता है, उसकी कीमत पर कोई भी विकास बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

सरकार गंगा संरक्षण के लिए कृत संकल्प : खंडूरी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद्र खंडूरी ने भी दावा किया कि वे और उनकी सरकार गंगा संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले आठ महीने में उनकी सरकार ने गंगा को बचाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। भविष्य में भी गंगा संरक्षण के लिए वृहद स्तर पर कार्य करने का संकल्प दोहराते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा के प्रति उनकी पूरी निष्ठा और आस्था है। उन्होंने कहा कि गंगा संरक्षण के लिए जनभावनाओं को घ्यान में रखते हुए प्रदेश की जरूरत के हिसाब से ही परियोजनाओं को संचालित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व हिन्दू परिषद और देश का संत समाज उन्हें गंगा संरक्षण से संबंधित जो भी सुझाव देगा, उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए ही कार्य किया जाएगा।

बाबा राम देव ने भी लिया गंगा बचाने का संकल्प

देश और दुनिया के लोगों की धड़कन बन चुके योग गुरू बाबा रामदेव ने भी अब गंगा को बचाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प के साथ बाबा ने सरकार को चुनौती दी है कि अगर सरकार ने गंगा नदी को प्रदूषित होने व उसका अस्तित्व बचाने के प्रयास नहीं किए तो गंगा रक्षक मंच के साथ मिलकर वे भी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। बाबा कहते हैं कि पतित पावनी गंगा का प्रदूषित हो जाना करोड़ों लोगों के जीवन एवं आस्था पर संकट है। उन्होनें चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो 18 सितम्बर से प्रचंड आंदोलन में शामिल होकर वे गंगा और राष्ट्र देव की आराधना में जुट जाएंगे।

भारतीय संस्कृति और पर्यावरण

प्रकृति के साथ सामंजस्य ही पर्यावरण प्रदूषण की भयावह समस्या का एक मात्र समाधान है।

■ डॉ विजय वशिष्ठ

आधुनिक युग में पर्यावरण प्रदूषण एक भयावह समस्या बन चुकी है। देश में वनों का विनाश हो रहा है, वन्य प्राणी लुप्त होते जा रहे हैं, फलस्वरूप पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है और हम विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के शिकार होते जा रहे हैं। मानवता का विनाश हो रहा है। प्राकृतिक असंतुलन का कारण हमारी बिगड़ती हुई मानसिकता है। यदि यही स्थिति रही तो शीघ्र ही यह पृथ्वी वन एवं वन्य जीवों से विहीन हो जाएगी तथा मानव विनाश को रोकना भी असंभव हो जाएगा।पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भारतीय जीवन दर्शन पर विचार करना आवश्यक है। हमारी संस्कृति पर्यावरण संवर्द्धन एवं संरक्षण वाली रही है। भारतीय संस्कृति प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीना सिखाती है। वेद, मनु स्मृति, धर्मशास्त्र एवं उपनिषदों के नियम इस तारतम्य की इच्छा एवं आवश्यकता को प्रदर्शित करते हैं।

वैदिक संहिताओं में ऋग्वेद प्राचीनतम् है, जिसमें मुख्य रूप से प्रकृति को ही देवी मान कर स्तुति की गई है। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति को माता माना है और कहा भी है–"माता भूमि अहं पुत्रोपृथ्वीया" भूमि ही प्रकृति का प्रथम तत्व है। पृथ्वी ही संपूर्ण भोगों की उत्पादिता है–इसीलिए इसे "श्री" कहा गया है। वेदों में वृक्षों के महत्त्व का सर्वाधिक प्रतिपादन किया गया है। इसीलिए वृक्षों में देवता का निवास माना गया है, तथा इनको न काटने पर बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में वट, पीपल, आंवला, तुलसी आदि का पूजन करने का भी यही अभिप्राय है कि ये मानव जीवन की सुरक्षा करते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाने की सलाह दी गई है, जिसका वैज्ञानिक कारण हैं कि तुलसी का पौधा ही संसार का एक मात्र ऐसा पौधा है जो दिन तथा रात दोनों समय ऑक्सीजन छोड़ता है तथा उसकी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा शोषित करती है। फलतः ऋषियों ने जनमानस में इस धारणा को बल दिया कि तुलसी में लक्ष्मी व विष्णु दोनों का निवास है।

वामन पुराण में तो प्रातःकाल उठते ही पांचों तत्वों का स्मरण करने की परम्परा पर जोर दिया गया है। पृथ्वी अपनी सुगंध, जल अपने बहाव, अग्नि अपने तेज, अंतरिक्ष (आकाश) अपने शब्द ध्वनि और वायु और अपने स्पर्श गुण के साथ हमारे प्रातः काल को अपना आशीर्वाद दे यही हमारी कामना है। गीता में भगवान ने प्रकृति को अष्टकोणी बताया है। पांच तत्वों के अलावा मन, बुद्धि एवं अहंकार की भी गणना की गई है। ये पांचों तत्व मिलकर मन और बुद्धि को निर्मल रखें तथा अहंकार को संयमित रखें। स्कंध पुराण के अनुसार जिस घर में प्रति दिन तुलसी की पूजा होती है उसमें यमदूत प्रवेश नहीं कर सकते (स्कंध पुराण 21.66)।

वाराह पुराण (172.39) में तो पेड़ पौधों और वनस्पतियों के रोपण–पोषण और संवर्द्धन को पुण्य कार्य माना गया है।

मंत्र में व्यवस्था है कि जो व्यक्ति अपने जीवनकाल में एक पीपल, एक नीम और एक बट का पेड़ लगाये, 10 फूलों वाले वृक्षों और लताओं का रोपण करे, अनार, नारंगी और आम के दो–दो वृक्ष लगाये, वह कभी नर्क में नहीं जाता। प्रकृति को धर्म से जोड़कर यह व्यवस्था की गई है कि व्यक्ति प्रकृति का विनाश न करे।

भारतीय संस्कृति में जल को पवित्र तथा पुण्य की वस्तु माना है। जल ही प्राण है। संपूर्ण प्राणियों, वनस्पतियों तथा औषधियों में सार तत्व के रूप में जल ही विद्यमान है। अतः इसे परम रस कहा गया है। यह सभी प्राणियों में प्राण का संचार करने के कारण प्राण कहलाता है। ऋग्वेद में जल को दिव्य तत्व मानकर वरूण को उसका देवता माना गया है। ऋग्वेद में जल के उचित प्रयोग का विशेष निर्देश दिया गया है अन्यथा यह दुरूपयोग करने वाले का ही नाश कर देता है। वर्तमान में जल प्रदूषित होता जा रहा है। हमारी पवित्र गंगा मां प्रदूषित हो रही है, इसी प्रदूषण को रोकने के लिए महाभारत में कहा गया है कि "जल में 33 कोटि देवता रहते हैं। अतः जल में मल–मूत्र त्याग सर्वथा वर्जित है। वर्तमान काल में भी जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल को दैवीय स्वरूप प्रदान कर उसकी शुद्धता यथावत रखने का प्रयास करने पर विशेष जोर दिया गया। अतः वृक्ष लगाकर जल भण्डार की वृद्धि करनी चाहिए।" पर्यावरण की शुद्धता के लिए वेदों में यज्ञ का बहुत महत्व प्रतिपादित किया है। ऋषियों ने यज्ञ को धर्म से संबद्ध कर दिया। प्रकृति में होने वाले विकार की मात्रा को दृष्टिपथ में रखते हुए उन्होंने यज्ञ की मान्यताओं को भी निश्चित कर दिया–जैसे दैनिक, पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक, वार्षिक इत्यादि। समय–समय पर आयोजित होने वाले इन यज्ञों से प्रकृति की शुद्धता, वर्षा की प्रचुरता, अन्न की उत्पत्ति इत्यादि कर्म व्यवस्थित होते रहते हैं। यज्ञ वातावरण के एक सीमित क्षेत्र को शुद्ध करते हैं, अर्थात् यज्ञ से उत्पन्न धुएं से नाइट्रोजन व अमोनिया गैस उत्पन्न होकर कार्बन डाइ ऑक्साइड को नष्ट करके वातावरण को शुद्ध करती है। घण्टानाद क्रिया के द्वारा उत्पन्न शब्द भी विषाणुओं का नाश करता है।

वर्तमान में व्याप्त पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का निदान यजुर्वेद के विधानों के अनुसार यज्ञ करने में है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी यज्ञों के महत्त्व को स्वीकारा है। वायु एवं प्रदूषण का घनिष्ठ संबंध है। भारतीय मनीषियों ने कहा "प्राण ही वायु है। वायु सभी जीवधारियों में प्रतिकारक तत्वों व अन्य पदार्थों की प्रेरक है। शतपथ में कथानक आता है कि सृष्टि के पूर्व सब ओर विद्यमान जल में वायु ने प्रवेश कर उसे आलोकित किया जिससे फेन की उत्पत्ति हुई तथा पुनः–पुनः आलोकित करने पर फेन से शिकता, शिकता से अश्मा (पत्थर) तथा अश्मा से इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। वायु प्रदूषण आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है। बड़े शहरों में शुद्ध वायु की उपलब्धि बहुत बड़ी समस्या है। भारतीय जीवन दर्शन में प्रकृति और संस्कृति को अलग–अलग करके देखना असंभव सा है। जहां तुलसी, वट एवं पीपल की पूजा, गाय का सम्मान, गंगा की स्तुति, सूर्य, चंद्र, मारूत, जल और पृथ्वी में देवत्व की कल्पना की गयी हो वहां प्रकृति के अपमान की बात सोची भी नहीं जा सकती। भारतीय संस्कृति में अनेक पर्व एवं त्यौहार पर हम वन्य जीवों की पूजा अर्चना करते हैं। मोर सरस्वती के साथ, सिंह महाकाली के साथ, बैल शिव के साथ, हाथी इंद्र के साथ, चूहा गणेश के साथ सदैव पूजनीय रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी बारह राशियों में से कई पशुओं के नाम पर हैं। भारतीय संस्कृति में वन्य प्राणियों को प्रमुख स्थान देकर प्रतिष्ठित ही नहीं किया बल्कि समय–समय पर लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर वनों एवं वन्य प्राणियों की रक्षा भी की है। राजस्थान में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां शासनादेश के बावजूद भी जनता ने एक भी पेड़ नहीं कटने दिया। जोधपुर जिले के गांव खेजड़ली में 363 बलिदानियों ने स्वयं के प्राणों की आहुति देकर पेड़ों की रक्षा की। ऐसा उदाहरण विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति ही हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना सिखाती है। आज की पर्यावरण प्रदूषण की भयावह समस्या का एकमात्र समाधान है कि भारतीय जीवन आदर्शों को मानते हुए प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्ण जीवन जीना। ❖

सेज के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच का अभियान

सरकार किसानों के हितों की चिंता करे : मुरलीधर राव

■ राजन चब्बा

हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के विधानसभा क्षेत्र गगरेट में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) स्थापित किये जाने के विरोध में गांव कुनेरन में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक मुरलीधर राव, प्रदेश संयोजक देश बंधु, राष्ट्रीय सदस्य कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पृथी सिंह वत्स, किसान संघ के कोषाध्यक्ष प्रो. के.आर. शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भगत राम पटियाल इत्यादि विशेष रूप से उपस्थित हुए।

इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक मुरलीधर राव ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सरकार, किसानों के हितों की चिंता नहीं कर रही, बल्कि किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब मात्र लाल किले पर तिरंगा फहरा देने का अधिकार मिलना ही नहीं है बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी इच्छा के अनुरूप देश व जनहित में कार्य करने का अधिकार मिलना है। जबकि आज के आजाद देश में किसानों के हितों पर सरकारें कुठाराघात कर रही हैं। मुरलीधर राव ने कहा कि अगर गौर किया जाए तो हम महसूस करते हैं कि किसानों का देश को चलाने में विशेष योगदान है लेकिन इस देश की सरकारें किसानों के हितों के प्रति अनदेखी कर किसानों की उपजाऊ भूमि को उजाड़ कर किसानों को तबाह करने का प्रसास कर रही हैं। उन्होंने चेताया कि आज यदि हम लोग व किसान अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा जिसके लिए जनआंदोलन करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि हम सब एकजुट होकर इस (एस.ई.जेड.) के विरोध में खड़े हो गए तो सरकार की हिम्मत नहीं कि जबरदस्ती किसानों की भूमि छीन सके।

इस मौके पर स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कश्मीरी

लाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि चीन ने अपने देश में मात्र 6 विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) स्थापित किए हैं और वह भी उस भूमि पर स्थापित किए गए हैं जो कि बिल्कुल बेकार पड़ी थी। उन्होंने बताया हमारे देश की सरकारें भारी संख्या में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की होड़ में लगी हैं और अब तक इस देश में लगभग 500 (एस.ई.जेड.) स्थापित किए जाने हेतु सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने एस.ई.जेड. के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं व खतरों के बारे में जानकारी देते हुए सेज के विरोध में लोगों से जोरदार संघर्ष करने का आह्वान किया।

अखिल भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पृथी सिंह वत्स ने अपने संबोधन में कहा कि यदि लोग स्वयं अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु एकजुटता से संघर्ष के मैदान में उतर जाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को गगरेट में एस.ई.जेड. (सेज) स्थापित करने के फैसले को बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने भारतीय किसान संघ से जुड़े देश भर के किसानों के सहयोग का आश्वासन भी दिया।

मातृभूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष नरेन्द्र परमार ने बताया कि गगरेट क्षेत्र के 24 गांव सेज की मार से प्रभावित होंगे तथा 80 हजार कवाल उपजाऊ भूमि किसानों से छिन जाएगी। उन्होंने संकल्प लिया कि वे किसी भी हालात में इस भूमि को छिनने नहीं देगें, उसके लिए चाहे उन्हें कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों न करना पड़े। उन्होंने ऐलान किया कि वह अपनी मातृभूमि बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इस मौके पर उपस्थित सैकड़ों लोगों ने सेज के विरोध में जमकर नारे बाजी की।

स्वदेशी जागरण मंच के प्रदेश संयोजक देश बंधु ने उपस्थित जनसमूह से हर संघर्ष में उनका साथ देने की बात कही। ❖

कृषि की अनदेखी से ही देश में खाद्य संकट

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के किसान प्रहरी सम्मेलन में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैय्या नायडू ने देश में गरीबी, भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट के लिए कृषि की अनदेखी को कारण मानते हुए इसके लिए कांग्रेस नीत यूपीए सरकार को जिम्मेदार बताया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के इस सम्मेलन में वेंकैय्या नायडू ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश पर 60 साल तक शासन किया है, जबकि महात्मा गांधी ने भी कहा था, ग्राम राज्य के बिना राम राज्य अधूरा है लेकिन कांग्रेस के शासन में गांव का विकास नहीं हुआ। गांवों को बर्बाद किया गया और कृषि की अनदेखी के कारण ही आज देश में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया है। सम्मेलन के इस मौके पर श्री नायडू ने यूपीए सरकार और सोनिया गांधी से सवाल किया कि वे जवाब दें कि 50 साल में उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। गांव और ग्रामीणों की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी गांवों में उपलब्ध नहीं हैं। कांग्रेस को किसान विरोधी पार्टी बताते हुए वेंकैय्या नायडू ने कहा कि सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और चिदंबरम को नहीं मालूम कि खेती क्या होती है। किसान रो रहा है और सरकार सो रही है। सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि अब तक इस देश में हजारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

यूपीए सरकार को कोमा में बताते हुए भाजपा नेता ने कहा कि सरकार वैंटीलेटर पर पड़ी है, जिसके चार प्रधानमंत्री हैं– पहले मनमोहन सिंह, दूसरे सीपीएम, तीसरी सुपर पीएम सोनिया गांधी और चौथे लालू प्रसाद यादव। इस प्रकार केंद्र की गाड़ी चलाने वाले अनेक चालक हैं, जो एक कदम आगे चलकर तीन कदम पीछे यूपीए सरकार को चला रहे हैं। इस भाजपा नेता ने पूर्ववर्ती राजग सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि गांव–गांव को जोड़ने का काम सड़क बनाकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया है। विभिन्न किसान हितैषी योजनाएं अटल की सरकार द्वारा लागू की गई हैं, जबकि केंद्र की यूपीए सरकार अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा पा रही। इस सरकार की ऋण माफी योजना भी अधूरी है, जिसका किसानों को लाभ नहीं मिला।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को आजादी के बाद की सबसे कमजोर सरकार बताते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इनकी समर्थक पार्टी कम्युनिस्ट संसद में हरा झंडा फहराती है और बाहर लाल। इस सरकार के मंत्री विभिन्न आरोपों से घिरे हैं, किसी पर लूट, किसी पर हत्या तो किसी पर चारा घोटाले का आरोप है। देश में उत्पन्न अनेक समस्याओं और संकट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। सोनिया गांधी के नाम पर बनी इस सरकार ने देश की जनता को धोखा दिया है। केंद्र सरकार महंगाई, कृषि क्षेत्र, आतंकवाद, उग्रवाद सहित किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाई। उन्होंने देश की जनता से आह्वान किया कि देश की भलाई के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाया जाना अब जरूरी हो गया है।

स्वदेशी जागरण मंच की बैठक में स्की विलेज का विरोध

राष्ट्रीय संयोजक बोले-जमीन खोना या भूमिहीन कर देना विकास नहीं

कुल्लू, 26 जून (थरमाणी) : जिला मुख्यालय स्थित राम सामुदायिक भवन में स्वदेशी जागरण मंच एवं किसान संघ ने कुल्लू में प्रस्तावित स्की विलेज एवं सेज के खिलाफ अपने तेवर कड़े करते हुए एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में विदेशी कम्पनियों द्वारा कुल्लू में बनाई जाने वाली परियोजनाओं के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच एवं किसान नेता जमकर बरसे। इस सम्मेलन में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक मुरलीधर राव ने मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। मुरलीधर राव ने उपस्थित जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि आज तक भारत का शोषण होता रहा है। जो भी आश्वासन देता वही धोखा करता आया है। उन्होंने कहा कि भारत को लंदन बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं किया गया। भारत का विकास हमारी इच्छाओं व संसाधनों के अनुसार होगा। उन्होंने कहा कि कुल्लू में अंग्रेजी हकूमत ने भी कब्जा नहीं किया था, आज विदेशी कम्पनियां ब्रिटिश सरकार से दो कदम आगे निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि जमीन खोना व भूमिहीन कर देना नहीं है। विकास के नाम पर किसानों की भूमि को छीना जा रहा है। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा ने अपना चोला उतार दिया है। विदेशी कम्पनियों से बचाना हमारी लड़ाई है, इसे हम ही लड़ेंगे। आज विदेशी कम्पनियां हमें बता रही हैं कि कुल्लू एवं हिमाचल का विकास कैसे होगा। सरकार कम्पनियों को जमीन खरीदने के लिए पैसे दे रही है, लेकिन किसानों के लिए ऋण नहीं है। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में भाजपा सरकार नही हैं, वहां भाजपा कहती है कि उपजाऊ जमीन किसानों से नहीं छीननी चाहिए, परन्तु यहां भाजपा को कृषि योग्य जमीन क्यों नहीं दिख रही हैं। उन्होंने कहा की स्की विलेज से स्थानीय व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी शंका जताई की यहां के कई नेताओं ने चुनावों के दौरान चुनाव लड़ने के लिए इस कम्पनियों से पैसा ऐंठा है, तभी स्की विलेज का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद के महासचिव महेंद्र ठाकुर, किसान संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पृथ्वी सिंह वत्स, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्य कश्मीरी लाल व प्रदेश संयोजक देश बंधु आदि ने भी लोगों को संबोधित किया और बहुचर्चित स्की विलेज एवं सेज के विरोध में जनता को जागरूक किया। ❖

बढ़ते कृषि मूल्यों पर अमीर देशों का कुतर्क

खाद्यान्न एवं ऊर्जा जरूरतों के लिए विकासशील देशों को अपने संसाधनों का विकास कर स्वावलम्बी बनना होगा।

■ डा0 भरत झुनझुनवाला

संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने 2005 में कहा था ''लम्बे समय तक कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट से विश्व के गरीबतम देशों की खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ गई है क्योंकि नकद के लिये कृषि उत्पादों का निर्यात् उनका एक मात्र साधन है।'' बांग्लादेश जैसे देश मुख्यतः जूट के निर्यात् पर निर्भर हैं। जूट के दाम में गिरावट आने से वे संकट में पड़ जाते हैं। अब एफएओ ने अपनी राय बदल दी है। अप्रैल 2008 में प्रकाशित रपट में कहा गया है ''विश्व के गरीबतम देशों द्वारा आयातित खाद्य पदार्थों के मूल्य में इस वर्ष 56 प्रतिशत वृद्धि होने को है। अफ्रीका के गरीबतम देश जो आयातित खाद्यान्न पर निर्भर हैं, उन्हें इस वर्ष ही 74 प्रतिशत उंचे मूल्य अदा करने पड़ रहे हैं। 37 देश खाद्यान्न संकट का सामना कर रहे हैं। कई विकासशील देशों में खाद्य पदार्थों को लेकर उपद्रव हो रहे हैं। इनमें अफ्रीका के मिस्त्र, केमरून, आइवरी कोस्ट, सोनेगल, इंडोनेशिया तथा फिलीपीन; एवं दक्षिण अमेरिका के हेट्टी शामिल हैं।''

एफएओ ने 2005 में कृषि उत्पादों के गिरते मूल्य को गरीब देशों के लिये संकट बताया था परन्तु 2008 में इन्हीं दामों में वृद्धि को संकट बता रहा है। वस्तुतः दोनों ही बातें सही हैं। सभी विकासशील देशों को समग्र रूप से देखा जाये तो कृषि मूल्यों में गिरावट उनके लिये हानिकारक है, जैसा 2005 में बताया गया था। सम्मिलित रूप से विकासशील देश कृषि उत्पादों का निर्यात् और औद्योगिक उत्पादों का आयात अधिक करते हैं। कृषि मूल्यों के उत्पादन में गिरावट आने से उन्हें

निर्यातों से आय कम मिलती है, जबकि औद्योगिक उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होने से उन्हें खर्च अधिक करना पड़ता है।

विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड डेवलपमेन्ट इंडिकेटर्स में दिये गये आंकड़ों से बात स्पष्ट हो जाती है। वर्ष 2004 में विकासशील देशों द्वारा किये गये निर्यातों में कृषि उत्पादों का हिस्सा 12 प्रतिशत था, तेल एवं खनिज का 23 प्रतिशत और औद्योगिक माल का 65 प्रतिशत। इन्हीं देशों के आयात्ों में कृषि उत्पादों का हिस्सा 10 प्रतिशत, तेल एवं खनिज का 15 प्रतिशत एवं औद्योगिक माल का 75 प्रतिशत था। कृषि, तेल एवं खनिज के मूल्यों में वृद्धि से विकासशील देशों को स्पष्ट रूप से लाभ होगा क्योंकि उनके निर्यातों में माल का हिस्सा 35 प्रतिशत है। मूल्य वृद्धि से 35 प्रतिशत निर्यातों में लाभ होगा जबकि 24 प्रतिशत आयातों में हानि। ऐसी ही स्थिति गरीबतम देशों की है। विश्व बैंक के अनुसार इन देशों द्वारा किये जा रहे निर्यात् में कृषि, तेल एवं खनिज का हिस्सा 46 प्रतिशत था जबकि आयातों में केवल 36 प्रतिशत।

2005 में एफएओ द्वारा कृषि उत्पादन में गिरावट को विकासशील देशों के लिये हानिप्रद बताना ठीक था। प्रश्न है कि 2008 में एफएओ ने अपनी राय क्यों बदल दी है? यदि 2005 में कृषि उत्पादों के मूल्य में गिरावट विकासशील देशों के लिये हानिप्रद थी तो 2008 में उनमें वृद्धि लाभप्रद होनी चाहिये थी। परन्तु वर्तमान में इस लाभ को गिनाने के स्थान पर एफएओ उन विशेष 37 गरीब देशों की बात कर रहा है जो कृषि उत्पादों का आयात अधिक और निर्यात् कम करते हैं। 2005 में जब कृषि उत्पादों के मूल्य गिर रहे थे तब इन 37 गरीबतम देशों को लाभ हो रहा था परन्तु उसे नहीं बताया गया। 2008 में जब कृषि उत्पादों के मूल्य बढ़ रहे थे तब इन 37 गरीबतम देशों के संकट को विशेष रूप से बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? कारण यह दिखता है कि 2005 में

जिन 37 गरीबतम देशों पर संकट बताया जा रहा है वे किसी समय अपनी खाद्य जरूरतों के लिये आत्मनिर्भर थे। उसी पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहिये। ऐसा करने से आयातों पर निर्भरता कम हो जायेगी और ये देश बढ़ते वैश्विक मूल्यों से बच जायेंगे।

अमीर देशों की स्थिति अच्छी थी। उन्हें कृषि, खनिज और तेल के गिरते दामों से लाभ हो रहा था। उनके आयातों में इन वस्तुओं का हिस्सा 20 प्रतिशत था, जबकि निर्यातों में 13 प्रतिशत। परन्तु उनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने से मूल्यों में गिरावट के कारण विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभाव से वे चिन्तित हो रहे थे, जैसे अमीर व्यक्ति गरीब की स्थिति पर चिन्तित होता है और मांगे गये 50 रू0 के स्थान पर करूणावश 60 रू0 दे देता है।

अब परिस्थिति बदल गयी है। आज अमीर देशों की अर्थव्यवस्थायें संकट में हैं, विशेषकर अमरीका की। वर्तमान में हो रही कृषि उत्पादों की मूल्य वृद्धि इन देशों के लिये हानिकारक है और विकासशील देशों के लिये लाभप्रद। परन्तु एफएओ जैसे संगठन अमीर देशों के हितों को बढ़ाते हैं। उनके लिये यह कहना सम्भव नहीं है कि वर्तमान मूल्य वृद्धि विकासशील देशों के लिये लाभप्रद है। अतः एफएओ उन विशेष 37 गरीबतम देशों की बात कर रहा है जो कि अमीर देशों की तरह कृषि उत्पादों का आयात कर रहे हैं। एफएओ मूल्य वृद्धि से विकासशील देशों को होने वाले लाभ की बात नहीं करता है क्योंकि इससे अमीर देशों को हानि होगी। जिस प्रकार मिल मालिक कैजुअल श्रमिकों के साथ संधि करके संगठित श्रमिकों की यूनियन को तोड़ता है और अन्त में सभी श्रमिकों के वेतन में कटौती करता है; उसी प्रकार एफएओ अमीर एवं 37 गरीबतम देशों के बीच समान हितों को बताकर सभी विकासशील देशों को डुबोने का कार्य कर रहा है। तब इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व बैंक एवं अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा लगभग ऐसे ही वक्तव्य दिये जा रहे हैं। हमें ठीक से समझ लेना चाहिये कि वर्तमान मूल्य वृद्धि हमारे हित में है क्योंकि हम कृषि उत्पादों का निर्यात अधिक एवं आयात कम करते हैं। हमें अपने हित से भटकाने के लिये ये संगठन मूल्य वृद्धि को 37 गरीबतम देशों के लिये हानिप्रद होने के कारण गलत ठहरा रहे हैं।

गरीबतम देशों का प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। इस समस्या के हल के लिये विकासशील देशों को दो बिन्दुओं पर विचार करना चाहिये। पहला बिन्दु यह कि सभी विकासशील देशों को प्रेरित करना चाहिये कि अपनी खाद्यान्न एवं उर्जा की जरूरतों की पूर्ति के लिये अपने संसाधनों का विकास करें और स्वावलम्बी बनें। विश्व बैंक आदि संस्थाओं ने पिछले दो दशकों में गरीब देशों को खुले व्यापार का मंत्र पढ़ाकर खाद्य पदार्थों के लिये आयातों पर निर्भर बना दिया है। मसलन भारत को बताया गया कि उसे कॉल सेन्टर की सेवाओं के निर्यात पर ध्यान देना चाहिये और मलेशिया से पाम ऑयल का आयात करना चाहिये। ऐसा होने पर हम पाम ऑयल के मूल्यों में वृद्धि से संकट में पड़ जाते हैं। हमें चाहिये था कि अपनी सभी मौलिक जरूरतों में स्वावलम्बी बने रहें और सरप्लस उत्पादन मात्र में विश्व व्यापार करें। जिन 37 गरीबतम देशों पर संकट बताया जा रहा है वे किसी समय अपनी खाद्य जरूरतों के लिये आत्मनिर्भर थे। उसी पुरानी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहिये। ऐसा करने से आयातों पर निर्भरता कम हो जायेगी और ये देश बढ़ते वैश्विक मूल्यों से बच जायेंगे।

दूसरा बिन्दु है कि भारत जैसे अग्रणी विकासशील देशों को 37 गरीबतम देशों के साथ अमीर देशों के विरूद्ध साझा रणनीति बनानी चाहिये। सभी विकासशील देशों को एकजुट होकर डबलूटीओ से पेटेन्ट व्यवस्था को बाहर निकालना चाहिये जिससे आधुनिक तकनीकों को डुप्लीकेट करने का पुराना अधिकार हमें वापस मिल जाये। विकासशील देशों द्वारा इस बिन्दु पर सहयोग के एवज में उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिये। सभी विकासशील देशों के बीच एकता बनानी चाहिये जैसे ट्रेड यूनियन का चतुर नेता कैजुअल एवं संगठित श्रमिकों के बीच एकता बना लेता है। ❖

सदस्यता सम्बन्धी सूचना

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है।

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	100/–	1000/–
अंग्रेजी	100/–	1000/–

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

सूचना

स्वदेशी पत्रिका साम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है, जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे व्यक्त कर सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। अच्छे लेख या रिपोर्ट पर पारितोषिक भी दिया जा सकता है। स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ सुधार या नए विषयों का समायोजन चाहते है कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

धर्मक्षेत्र, सेक्टर-8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली-110022

ठोस नीति के अभाव का नतीजा है

सब्सिडी के बोझ तले दबी सरकार

'सेज' की बचनबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को कर छूटों को कम करने के लिए बहुत अधिक साहस जुटाने की जरूरत पड़ेगी।

■ रूद्रदत्त

अब से लगभग एक दशक से भी ऊपर हो गया है जब सब्सिडी पर एक चर्चापत्र सार्वजनिक वित्त एवं नीति के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 1997 में पेश किया गया। तत्पश्चात् परिस्थिति में भारी परिवर्तन हुआ है और इस मुद्दे का पुनः निरीक्षण करने की ज़रूरत है। इसके मुख्य कारण हैं :–

अव्यक्त अर्थसाहाय्यों में विभिन्न रूप में केंद्र और राज्य स्तर पर वृद्धि हुई है। उदाहरणार्थ, विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बहुत–सी कर–छूटें दी गईं हैं। इसका परिणाम कर–राजस्व में भारी हानि है।

एक दूसरा उदाहरण राज्य सरकारों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए भूमि–अधिग्रहण कर इसे बड़े औद्योगिक घरानों को सौंपना है।

पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपने ओद्योगिकीकरण के अभियान में टाटा घराने के सिंगूर प्रोजैक्ट के लिए निम्नलिखित अर्थसाहाय्य दिए।

सिंगूर में भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहण कर टाटा को 90 वर्ष के पट्टे पर दी गई, इस पर कोई तात्कालिक भुगतान नहीं करना था। दूसरे, पहले पांच वर्षों में टाटा सिर्फ एक करोड़ रूपये देंगे। और इस भुगतान में 25 पंतिशत की वृद्धि पांच वर्षों तक की जाएगी जो अगले 25 वर्षों तक जारी रहेगी। अगले 30 वर्षों के इस भुगतान में प्रत्येक पांच वर्षों के बाद 38 प्रतिशत की वृद्धि होगी और अंतिम 20 वर्षों के लिए 20 करोड़ रूपये प्रति वर्ष देने होंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार टाटा को 200 करोड़ रूपये 1 प्रतिशत ब्याज दर पर उधार देगी, जबकि कारों के विक्रय पर मूल्य वृद्धि कर पहले 16 वर्षों की अवधि के लिए टाटा को वापस कर दिया जाएगा। इस सबके विरुद्ध किसानों की कुल क्षति पूर्ति के लिए 200 करोड़ रूपये दिए जाएंगे।

ओद्योगिकीकरण द्वारा विकास के इस मॉडल के विरुद्ध आलोचकों ने यह सवाल उठाया है कि क्या हम विकास भी समावेशी नीति के आधीन किसानों, फसल–सहभाजकों और संबंधित अन्य व्यक्तियों की जो भूमि पर निर्भर हैं, आजीविका छीन रहे हैं, और इसके विरुद्ध, उद्योग को सरकार की ओर से भारी साहाय्य, साहाय्य–प्राप्त–पावर, उदार कर–अवकाश, संयत्र खरीदने के लिए वित्तीय आलंबन, साहाय्यित उधार और निर्यात के लक्ष्य से छूट आदि दी जा रही है।

इसी प्रकार सरकार कृषि के लिए निःशुल्क बिजली मुहैय्या कराती है, जिसका लाभ मुख्यतः बड़े किसान उठाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि कर–छूटों के परिणामस्वरूप 2,78,644 करोड़ रुपये की राजस्व हानि होगी–यह बहुत बड़ी राशि है। सरकार निगम कर से प्राप्ति में वृद्धि के लिए निगम क्षेत्र की प्रशंसा करती है परंतु तथ्य यह व्यक्त करते हैं, कि चाहे निगम कर की दर 30 प्रतिशत निश्चित की गई है परंतु इसकी प्रभावी दर केवल 19 प्रतिशत है। प्रभावी दर में निश्चित दर की तुलना में तीव्र कमी के कारण निगम क्षेत्र को विभिन्न रूप में दी गई कर–छूटें हैं।

अन्य अर्थसाहाय्यों की वैधता पर विचार करने की आवश्यकता है जो गैर–सर्वहितकारी सरकारी साहाय्यों का

भाग हैं।

पेट्रोलियम अर्थसाहाय्य की स्थिति में भारी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि पेट्रोलियम की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई है। यदि सरकार इस अर्थसाहाय्य को पूर्ण रूप में उपलब्ध कराती है तो इस अर्थसाहाय्य की राशि 1,50,000 करोड़ रूपये हो जाएगी। परिणामतः राजकोषीय घाटा जी.डी.पी. के 3.2 प्रतिशत से बढ़ जाएगा। सरकार इस समस्या का आंशिक रूप में समाधान करने के लिए कुल अर्थसाहाय्य का 50 प्रतिशत बांडों के रूप में दे सकती है और परिणामतः बांडों पर ब्याज ही बजट में लागत के रूप में प्रतिबिंबित होगा। परंतु जब ये बांड परिपक्व हो जाएंगे, इनके ऋणशोधन के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा।

सरकार के पास पैट्रोलियम के आयात पर सब्सिडी स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। वह देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ा सकती है, और उसने ऐसा ही किया है

4.उर्वरक साहाय्य के रूप में परिस्थिति कोई बेहतर नहीं है। उर्वरकों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, देशीय कीमत का 4–5 गुना है। उर्वरक साहाय्यों का संभावित प्रभाव लगभग 80,000 करोड़ रूपये होगा जबकि 2008–09 के बजट में इसके लिए 30,000 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

5.ऐसी ही परिस्थिति खाद्य साहाय्यों के लिए है। खाद्यान्नों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में तीव्र वृद्धि हुई है। देश में अभाव को दृष्टि में रखते हुए भारत ने 10 लाख टन अनाज आयात करने का निर्णय लिया है, ताकि समाज के कमज़ोर वर्गों को साहाय्यित दरों पर खाद्यान्न मुहैय्या कराया जाए। अतः जबकि 2008–09 में खाद्य–अर्थसाहाय्य के रूप में बजट में 32,666 करोड़ रूपये का प्रावधान है, अर्थसाहाय्य की वास्तविक राशि इससे कहीं अधिक होगी।

वित्त मंत्री ने 2008–09 के बजट में अर्थसाहाय्यों के लिए 66,537 करोड़ रूपये का प्रावधान किया–खाद्य साहाय्य 32,666 करोड़ रूपये, उर्वरकों के लिए 30,986 करोड़ रूपये और पेट्रोलियम के लिए 2,885 करोड़ रुपए। परंतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कारण तत्वों ने इस पूर्वानुमान को अस्त–व्यस्त कर दिया। पेट्रोलियम क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को बांड जारी करने से देश इस भार को कुछ वर्षों के लिए आंशिक रूप में टाल सकता है। इसके बावजूद, विशेषज्ञों का अनुमान है कि खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम साहाय्य 1,50,000 करोड़ रूपये से भी अधिक हो जाएंगे और यह जी.डी.पी. के 4–5 प्रतिशत तक पहुंच जाएंगे। अतः परिस्थिति अत्यंत गंभीर है।

परंतु अब प्रश्न उठता है कि नीति संबंधी विकल्प क्या है? सरकार के पास पेट्रोलियम के आयात पर अर्थसाहाय्य स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। वो देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ा सकती है, और उसने ऐसा ही किया है–पैट्रोलियम की कीमतें 5 रूपये प्रति लीटर डीज़ल की 3 रूपये प्रति लीटर और रसोई गैस की कीमत 50 रूपये प्रति सिलेंडर बढ़ाई है। इससे भी सरकार का भार आंशिक रूप में ही कम होगा। पेट्रोलियम आयात को कम करने का विकल्प उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऑटोमोबाइल उद्योग का उत्पादन और लोगों की मांग बढ़ती जा रही है–मोटर साइकिलों, तिपैहया गाड़ियों और कारों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है। खाद्य और उर्वरकों के संबंध में उपभोक्ताओं से अधिक वसूल करने की संभावना बहुत ही कम है क्योंकि मिली–जुली सरकार को 2009 में आम चुनाव का सामना करना है। अतः सरकार को उद्योग को बड़े पैमाने पर दी गयी कर–छूटों के बारे में निर्णय लेना है ताकि यह अपने राजस्व को बढ़ा सके। परंतु विशेष आर्थिक क्षेत्र की परियोजनाओं पर की गई वचनबद्धता को दृष्टि में रखते हुए सरकार को इन छूटों को कम करने के लिए बहुत अधिक साहस जुटाना होगा।

अतः सरकार के पास एक ही विकल्प शेष रह जाता है, कि अर्थसाहाय्यों पर एक व्यापक चर्चा पत्र तैयार करे–इसमें केंद्र तथा राज्य सरकारों के सभी अर्थसाहाय्यों को शामिल किया जाए। इसमें व्यक्त और अव्यक्त अर्थसाहाय्य दोनों शामिल किए जाएं। इस पर एक राष्ट्रीय बहस कराने से संभवतः एक मत कायम किया जा सके कि अर्थसाहाय्यों (सब्सिडीज) के बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन विकल्प क्या है। ❖

बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार कौन?

कांग्रेस को बहाने की तलाश, मुद्रास्फीति का ठीकरा किस के सर फोडे।

■ डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

20 जून 2008 को समाप्त हुए सप्ताह में मंहगाई (मुद्रास्फीति) ने गत 13 वर्षों में सर्वाधिक आंकडा 11.05 प्रतिशत प्राप्त कर लिया। देश की अर्थव्यवस्था इस समय विश्व प्रसिद्ध तीन अर्थशास्त्रियों– प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम् व योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया के द्वारा बतायी व निर्धारित की गई रीति व नीतियों पर चल रही है, जिसका दुष्परिणाम आम आदमी बढती मुद्रास्फीति के रुप में भुगत रहा है। निकट भविष्य में आम आदमी को मुद्रास्फीति से कोई राहत भी मिलती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की सुप्रीमो श्रीमती सोनिया गांधी बढ़ती मुद्रास्फीति के लिए एक अदद बहाने (सर) की तलाश कर रही हैं, जहां मुद्रास्फीति का यह ठीकरा फोड़ा जा सके तथा कहा जा सके कि मुद्रास्फीति के लिए कांग्रेस की रीति व नीति जिम्मेदार नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी कह रही हैं कि इस बढती मुद्रास्फीति के लिए केन्द्र सरकार की नीतियां जिम्मेदार नहीं हैं अपितु राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं जो कि बाजार पर नियंत्रण नहीं रख सकी हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति के लिए कांग्रेस कभी विश्व व अमेरिका में आयी मंदी को, कभी भारतीय रुपये में आयी मजबूती को, कभी पेट्रोलियम पदार्थों की बढी कीमतों को, कभी सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते मंहगाई भत्ते की किश्तों को, कभी किसानों के द्वारा अपनी उपजों के लिए मांगे जाने वाले बढ़े हुए समर्थन मूल्यों सहित अनेक कारणों को जिम्मेदार ठहरा रही है परन्तु बढती मुद्रास्फीति का कोई भी कारण साबुन की बट्टी की तरह हाथ से फिसल जाता है तथा कांग्रेस ही कठघरे में खडी दिखाई देती है। कांग्रेस के सामने आगामी आम चुनावों में जीत की समस्या भी खडी हो गई है। विपक्षी दल भी बढती महंगाई पर राजनीति करते हुए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व अन्य जिम्मेदार मंत्रियों से त्यागपत्र की पुरजोर मांग करने लगे हैं, कि अब ये लोग अपनी अच्छी सेवाओं से भारत के लोगों को बख्श दें जिनके चलते देश में बढ़ती मुद्रास्फीति के दावानल की आग लगी है।

बढ़ती मुद्रास्फीति का सबसे बडा प्रतिकूल असर उद्योगों पर पड़ेगा। बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार ब्याज दरों मे वृद्धि कर सकती है, जिससे उद्योगों के सामने स्थायी व कार्यशील पूंजी की समस्या खडी होगी और उद्योगों का विकास अवरुद्ध हो जायेगा। बढ़ती मुद्रास्फीति से कम्पनियों का लाभ घट जायेगा। कम्पनियां बढ़ी हुई कीमतों का भार उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित कर देंगी तो उससे उत्पादों की मांग कम हो जायेगी, अर्थव्यवस्था में और गिरावट आ जायेगी तथा उद्योगों के सामने मुश्किलें बढ़ेंगी। बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकारी कदमों से अगर जीडीपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो देश का मकान

कारोबार व उपभोक्ता दोनों को ही मौद्रिक, राजकोषीय व प्रशुल्क नीतियों के साथ–साथ बैंकों के द्वारा उदार होकर ऋण देने की प्रवृति तथा सरकार के द्वारा वोट बैंक की राजनीति करते हुए बैंकों के दिये गये ऋणों को आम माफी के द्वारा न चुकाये जाने की बढ़ती प्रवृति ने मंहगाई की ज्वाला को और भड़काने में अपना भरपूर सहयोग दिया है। सरकार के गत दो–तीन महीनों में लिये निर्णयों से बढ़ती मुद्रास्फीति में अभी 2 प्रतिशत तक और बढ़ोतरी की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

निर्माण उद्योग और विशेषकर सीमेंट उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उद्योग संघ की प्रमुख संस्था एसोचैम ने तो यहां तक कहा है कि बढ़ती मुद्रास्फीति विकास को खा रही है। सरकार भी हताश व निराश दृष्टि से अनियत्रित बढ़ती मुद्रास्फीति को देख भर रही है। एसोचैम ने कहा है कि बढ़ती मुद्रास्फीति की दर सरकार ही नहीं अपितु सम्पूर्ण उद्योग जगत के लिए चिन्ता की बात बनती जा रही है। तेरह वर्ष में अपने उच्चतम शिखर पर पंहुची मुद्रास्फीति को काबू करना सरकार के बस के बाहर की बात हो गई है। बढ़ती मुद्रास्फीति में सहयोग कर रही कई चीजें (घटक) सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इससे विकास को भी गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। फिक्की का मानना है कि जीडीपी व विकास की दर सरकार के लिए गम्भीर चुनौती खड़ी कर रही है। फियो (फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स) का मानना है कि बढ़ती मुद्रास्फीति से भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्द्धी क्षमता कम हो सकती है तथा निर्यात के मोर्चे पर गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। घरेलू इनपुट लागतों में बढोतरी से वस्त्र, चर्म उत्पाद, हस्तशिल्प, सांमुद्रिक उत्पाद, कृषि उत्पादों इत्यादि उद्योगों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सीआईआई (भारतीय उद्योग परिसंघ) के अनुसार अतंर्राष्ट्रीय रुख के अनुसार ही भारत में अप्रत्याशित मुद्रास्फीति हुई है, लेकिन यह मौद्रिक एवम् राजकोषीय नीति के कुशल प्रबंधन की गुंजाइश को बहुत कम कर देती है।

उधर, देश के अधिकांश राजनीतिक दलों ने भी बढती मुद्रास्फीति के कारण आम आदमी को हो रहे कष्टों पर चिन्ता व्यक्त की है। देश के प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रुडी ने तो यहां तक कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री देश को अपनी सेवाओं से मुक्त कर दें। स्वयं वित्त मंत्री पी चिदम्बरम् भी बढ़ती मुद्रास्फीति को लेकर चिन्तित हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार लोगों की परेशानियों से वाकिफ है। मौद्रिक नीतियों को और कठोर करना होगा। सरकार के साथ गठबंधन में शामिल रहे गरीब, श्रमिक वर्ग के हितैशी समझे जाने वाले वामपंथी दल के प्रकाश कारत ने कहा है कि बढ़ती मुद्रास्फीति पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतो में हुई वृद्धि का परिणाम है, परन्तु वैश्विक महंगाई का बहाना करके केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक तूफान सा महसूस किया जा रहा है जिसके अनेक कारण हो सकते हैं जो देश के सामने एक–एक करके आये। गत एक वर्ष के दौरान ही पेट्रोलियम उत्पादों के दाम जबरदस्त ढंग से बढ़े। ईधन के लिए भारत आयात पर ही निर्भर है। ईधन की खपत को देखते हुए ईधन के आयात को कम नहीं किया जा सकता जिससे बढ़ती मुद्रास्फीति का आंकड़ा दहाई को छू गया। कारोबारी घाटा बढ़ गया, राजकोषीय घाटा भी दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। देश में बढ़ती मुद्रास्फीति से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है तथा निकट भविष्य में यह और होने की आशा जताई जा रही है। परन्तु बैंकों की जमाओं पर ब्याज दरें अभी भी नहीं बढ़ी है। इन जमाओं पर ब्याज दरों को आने वाले समय में बढ़ाना ही होगा, नहीं तो बैंकों को नकदी की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। राजकोषीय घाटा बढने से अगर ब्याज दरें बढ़ी तो परिणाम नुकसानदायक हो सकते हैं।

बढ़ती मुद्रास्फीति का असर भारत के स्टॉक एक्सचेंज के कारोबार पर भी पड़ा है। भारत में प्राथमिक शेयर बाजार बुरी हालत में पहुंच गया है तथा शेयर कारोबार वॉल्यूम में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी जा रही है। वैश्विक आर्थिक मंदी तथा अमेरिकी बाजार में वित्तीय संकट से भारत का पूंजी बाजार भी प्रभावित हो रहा है। बढ़ती मुद्रास्फीति में अनेक घटकों व कारणों ने अपना भरपूर योगदान दिया है। कारोबार व उपभोक्ता दोनों को ही मौद्रिक, राजकोषीय व प्रशुल्क नीतियों के साथ–साथ बैंकों के द्वारा उदार होकर ऋण देने की प्रवृति तथा सरकार के द्वारा वोट बैंक की राजनीति करते हुए बैंकों के दिये गये ऋणों को आम माफी के द्वारा न चुकाये जाने की बढ़ती प्रवृति ने मंहगाई की ज्वाला को और भड़काने में अपना भरपूर सहयोग दिया है। सरकार के गत दो–तीन महीनों में लिये निर्णयों से बढ़ती मुद्रास्फीति में अभी 2 प्रतिशत तक और बढ़ोतरी की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

वर्तमान आर्थिक परिस्थिति में तो कांग्रेस व भाजपा दोनों को ही मिलकर बढ़ती मुद्रास्फीति से लड़ना चाहिए, जिससे आम भारतीय जनता को राहत दी जा सके। कांग्रेस को भी बहाने की तलाश में समय नही गंवाना चाहिए। ❖

चीन पर अधिक विश्वास भारत के हित में नहीं

तिब्बत के मामले में विदेश मंत्री की चुप्पी का सबब!

■ डॉ कुलदीप चन्द अग्निहोत्री

भारत के विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी पिछले माह चीन की आधिकारिक यात्रा करके आए हैं। जब से पश्चिमी देशों ने और वहां के अर्थशास्त्रियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि भारत और चीन दोनों मिलकर विश्व की नई धुरी के रूप में उभर सकते हैं तब से लगता है कि भारत का चीन के प्रति विश्वास बहुत बढ़ गया है। अपने यहां वैसे भी नेताओं को भूलने की बीमारी बहुत है। चीन के मामले में तो भारत सरकार 1962 को भूलने का प्रयास कर ही रही है। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री कभी भी चीन के साथ उस भारतीय क्षेत्र का प्रश्न नहीं उठाते जिस पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था।

दूसरा प्रश्न तिब्बत का है। तिब्बत के मामले में भारत सरकार चीन के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रही है मानो उसने तिब्बतियों को अपने यहां शरण देकर चीन के साथ कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तिब्बत के प्रश्न पर हमारी सरकार चीन के आगे क्षमायाचक की मुद्रा में ही खड़ी दिखाई देती है। इसलिए कभी भारत सरकार का कोई मंत्री बीजिंग में तिब्बत का प्रश्न भी उठाएगा ऐसी कल्पना करना ही शेरनी का दूध लाने के बराबर होगा। प्रणव मुखर्जी अपनी इस चीन यात्रा के दौरान इसी प्रकार का व्यवहार करते दिखे। वे भूकंप पीडितों के लिए राहत सामग्री बांट रहे थे। एक नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कर रहे थे। भारत चीन के हजारों वर्षों के मधुर और शांतिपूर्ण संबंधों पर खुद ही तालियां पीट रहे थे। लेकिन चीन के लोग इतने भुलक्कड़ नहीं हैं।

चीन के विदेश मंत्री ने सीमा विवाद के पुराने मुद्दे तो उठाए ही साथ ही इस बार सिक्किम के कुछ क्षेत्र को भी चीन का हिस्सा बताकर उस क्षेत्र को भी सीमा विवाद से जोड़ने का प्रयास किया। कहा जाता है कि प्रणव मुखर्जी ने चीन के सिक्किम के दावे को नकारा परंतु चीन की कूटनीति पर इसका कोई असर नही पड़ता है। एक बार उसने मुद्दा उठा लिया है तो अब वह नियमित रूप से इसको विवाद की श्रेणी में रखकर उठाता रहेगा। विवाद बढ़ाने का यह चीन का सदियों पुराना आज़माया हुआ नुस्खा है। चीन एक बार किसी मुद्दे को उठाता है और हर बार उसको रिकॉर्ड में लाता रहता है और फिर तीस–चालीस या पचास साल के बाद वह कहना शुरू कर देता है कि यह सीमा विवाद बहुत पुराना है और इसको पुराना सिद्ध करने के लिए उसके पास अपना रिकॉर्ड तो होता ही है।

तिब्बत पर अपना अधिकार जताने के लिए भी चीन ने इसी प्रकार के नुस्खों का प्रयोग किया था। सिक्किम के इस हिस्से के बारे में भी उसने प्रणव मुखर्जी को बताया है कि उसके रिकॉर्ड के अनुसार 1890 से ही यह हिस्सा चीन के प्रशासनिक

अधिकार में है। चीन सीमा विवाद का क्षेत्र बढ़ाता जाएगा और इस विवाद को वह सैकड़ों साल तक भी जिंदा रख सकता है, क्योंकि इसमें उसे कुछ खोना नहीं है। केवल भारत और भारतीय सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। प्रणव मुखर्जी जैसे लोगों के पास चीन की इस कूटनीति की कोई काट नही है। इसे इतिहास का संयोग ही कहें कि सैकड़ों साल पहले भारत तिब्बत सीमाओं का सर्वेक्षण बंगाली बाबुओं ने ही किया था और आज 2008 में भी एक बंगाली बाबू इन्हीं सर्वेक्षण के पेंचों में गिरकर हांफ रहा है। चीन इस प्रकार की बातों में आक्रामक रहा है।

प्रणव मुखर्जी के इस दौरे में चीन के प्रधानमंत्री ने तो उनसे अपनी भेंटवार्ता रद्द ही कर दी। बहाना यह था कि प्रधानमंत्री भूकंपग्रस्त क्षेत्रों में जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री ने जरूर खरे और स्पष्ट शब्दों में प्रणव मुखर्जी से पूछा कि भारत सरकार दलाई लामा और तिब्बतियों को इतना बोलने की छूट क्यों दे रही है? भारत का मीडिया तिब्बत और दलाईलामा को इतनी कवरेज क्यों दे रहा है? भारत और चीन द्विपक्षीय बातों में चीन की भूमिका आक्रमण करने की रहती है और भारतीय पक्ष अपनी सफाई देता रहता है। प्रणव मुखर्जी की इस यात्रा से भी यही संकेत मिलते हैं। प्रणव मुखर्जी ने इस यात्रा में कश्मीर के उस हिस्से का प्रश्न भी उठाया जो पाकिस्तान ने चीन को दिया हुआ है। लेकिन चीन के विदेश मंत्री की दादागिरी काबिले गौर थी। उसने कहा इस मुद्दे पर सचिव स्तर के लोग बातचीत कर सकते हैं। सिक्किम के मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री खुद बातचीत करना चाहते हैं। परंतु चीन द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र पर सचिव स्तर की ही बातचीत जारी रखने चाहते हैं।

यदि प्रणव मुखर्जी की इस चीन यात्रा का एक वाक्य में मूल्यांकन करना हो तो कहा जा सकता है कि प्रणव मुखर्जी सिक्किम को विवादास्पद बनाकर वापस लौट आए हैं। वैसे भी अब चीन की मुद्रा और व्यवहार भारत को सलाह देने या उसका मार्गदर्शन करने जैसी होती जा रही है। चीन के विदेशमंत्री ने भारत को यह सुझाव दिया कि उसकी इच्छा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों बैठकर आपसी समस्या सुलझाएं। प्रणव दादा यह हिम्मत नहीं जुटा पाए कि चीन के विदेश मंत्री यांग जिशी से कह देते कि तिब्बत और चीन मिल बैठकर आपसी समस्या सुलझाए। जहां तक दूसरे पक्ष का अपमान करने का प्रश्न है, उसका भी चीन के पास पुराना आजमाया हुआ फॉर्मूला है। जब पुराने विदेशमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी चीन यात्रा पर गए थे तो चीन ने वियतनाम पर हमला कर दिया था। यह शुक्र है कि प्रणव मुखर्जी के बहाने भारत को नीचा दिखाने के लिए चीन ने इस बार किसी पड़ोसी देश पर हमला नहीं किया। अलबत्ता प्रणव मुखर्जी की अपने प्रधानमंत्री से मुलाकात को रद्द कर दिया और इसके जवाब में कहा गया कि आप उपराष्ट्रपति से मिल लीजिए। चीन के सत्ता तंत्र में उपराष्ट्रपति की क्या औकात, है यह कोई बी. ए. प्रथम वर्ष का छात्र भी बता देगा। प्रणव मुखर्जी भी कह सकते थे कि उपराष्ट्रपति से मिलने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन इस प्रकार कहने के लिए जो गुर्दा चाहिए वह भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में पिछले साठ वर्षों से गायब है। भारत–चीन के मध्य बातचीत हो इसका कोई विरोध नही करता लेकिन बातचीत बराबर के स्तर पर होनी चाहिए और उसी भाषा का प्रयोग भारत को करना चाहिए जिस भाषा का प्रयोग चीन कर रहा है। यदि चीन तिब्बत की स्वतंत्रता की बात को स्वीकार नहीं करता तो भारत का कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र पर ऐतिहासिक और वैधानिक दावा बनता है। भारत को यह दावा अवश्य करना चाहिए।

भारत–चीन के मध्य बातचीत हो इसका कोई विरोध नही करता लेकिन बातचीत बराबर के स्तर पर होनी चाहिए और उसी भाषा का प्रयोग भारत को करना चाहिए जिस भाषा का प्रयोग चीन कर रहा है। यदि चीन तिब्बत की स्वतंत्रता की बात को स्वीकार नहीं करता तो भारत का कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र पर ऐतिहासिक और वैधानिक दावा बनता है। भारत को यह दावा अवश्य करना चाहिए।

डॉ० राम मनोहर लोहिया ने एक अरसा पहले कहा था यदि कैलाश मानसरोवर तिब्बत में रहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यदि कैलाश मानसरोवर पर चीन कब्जा करता है तो भारत को अवश्य इस क्षेत्र को छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। फिलहाल छुड़ाने की बात तो दूर भारत यदि इस पर अपना दावा ही करता है तो चीन की, कूटनीति का सही जवाब दिया जा सकता है। रही बात संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता की, चीन के विदेश मंत्री ने प्रणव मुखर्जी को बताया कि हम भारत की महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं और समय आने पर सही निर्णय लेंगे। बच्चे को टॉफी देते समय लगभग इसी भाषा का प्रयोग बड़े करते हैं, लेकिन बीजिंग में खड़े प्रणव मुखर्जी इतना तो समझ रहे होंगे कि भारत की उम्र अब टॉफी खाने की नहीं रही। तिब्बत का प्रश्न उठाकर भारत इस टॉफी इटिंग की भूमिका से बाहर आ सकता है और उसे आना भी चाहिए। ❖

तिब्बत की मुक्ति में ही भारत का हित

तिब्बत समर्थक भारतीयों का संकल्प : राष्ट्र सुरक्षा की कीमत पर चीन के साथ कोई समझौता मंजूर नहीं

■ **आर. पी. दुबे**

चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय तिब्बत समर्थकों के सम्मेलन में देशभर से एकत्रित हुए बुद्धिजीवी, नेता, व्यापारी, कर्मचारी, वकील, अध्यापक और पत्रकार तथा अलग–अलग क्षेत्रों से आए तिब्बत समर्थकों ने यह स्वीकार किया कि तिब्बत की स्वतंत्रता में ही भारत की सुरक्षा निहित है, और यह संकल्प लिया कि राष्ट्र की सुरक्षा की कीमत पर चीन के साथ उन्हें कोई समझौता मंजूर नहीं।

दो दिवसीय इस राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वायत्तता अथवा स्वतंत्रता को लेकर नेताओं में अवश्य ही मतभेद दिखा लेकिन तिब्बत समर्थक कोई भी कार्यकर्ता इस बात के लिए राजी नहीं था कि तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर चीन के साथ किसी प्रकार का समझौता हो। तिब्बत की समस्या अकेले तिब्बत की नहीं है, बल्कि भारत सहित तमाम उन देशों की है जो कमजोर हैं और चीन की उन पर गिद्ध नजर है। इसके साथ ही अधिकांश वक्ता इस बात पर एकमत थे कि भारत का हित और अहित तिब्बत के साथ जुड़ा है, इसलिए जब तक तिब्बत पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, भारत भी सुरक्षित नहीं रह सकता। सम्मेलन के माध्यम से तिब्बत समर्थकों ने भारत सरकार पर भी दबाव बनाया कि वह तिब्बत के मामले में अपनी नीति स्पष्ट करे, नीति में सुधार करे और इस पर भी विचार करे कि आखिर तिब्बत में क्या हो रहा है और जो हो रहा है क्या उचित है। तिब्बत समर्थकों का इस बात पर विशेष जोर था, कि भारत सरकार तिब्बत को नष्ट करने की चीन की कोशिश के खिलाफ अपना नैतिक कर्तव्य समझकर तिब्बत का सहयोग करे और चीन से उसे मुक्ति दिलाए।

सम्मेलन में उपस्थित लगभग सभी प्रमुख वक्ताओं का यह मत था, कि चीन से तिब्बत की मुक्ति केवल तिब्बत की मुक्ति नहीं है बल्कि यह भारत की सुरक्षा, भारत का विकास, भारत की संस्कृति एवं संप्रभुता से जुड़ा विषय है, जिसमें सभी का हित है। तिब्बत की आजादी का मतलब है सत्य, अहिंसा और न्याय की जीत, जो भारत की परंपरा रही है, तिब्बत का संघर्ष राजनीति का झगड़ा नहीं है, सत्ता का संघर्ष भी नहीं है बल्कि प्रत्येक राष्ट्रभक्त का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह न्याय और धर्म के पथ पर चलने वाले का सहयोग करे।

सत्र की शुरूआत मुख्य अतिथि व पूर्व केंद्रीय मंत्री यंशवत सिन्हा के दीप प्रज्ज्वलन के बाद धर्म साधना कर रहे आचार्यगणों द्वारा मंगलाचरण से हुई। मुख्य अतिथि श्री सिन्हा ने 450 से अधिक तिब्बत समर्थकों में उत्साह का संचार करते हुए यह कहकर उन्हें प्रेरित किया कि जनांदोलन से जुड़ने की उम्र सीमा नहीं होती। वीर कुंवर सिंह ने तो 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे। श्री सिन्हा ने कहा कि तिब्बत का आंदोलन नाजुक दौर से गुजर रहा है और

17 अप्रैल 1959 में दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एक भाषण में कहा था कि दो देशों की दोस्ती का मतलब यह नहीं कि उनमें कभी मतभेद न हो। सरकारें कमजोर होती हैं, जनता कमजोर नहीं होती इसीलिए तिब्बत का जनांदोलन आज जीवित है।

भारत में हम सब इस आंदोलन से जुड़े हैं इसलिए हम सभी को सही दिशा में सही निर्णय लेना होगा। तिब्बत की बातचीत सार्थक मोड़ तक पहुंचे, इसके लिए समर्थकों को अपना मनोबल मजबूत रखना होगा। यदि समर्थक कमजोर होगा तो चीन के साथ दलाईलामा की बातचीत सार्थक नहीं हो सकती।

तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री सामदोंग रिनपोछे की प्रशंसा करते हुए भाजपा नेता श्री सिन्हा ने कहा कि किसी के लिए भी इतनी बड़ी बात कहना संभव नहीं है जो श्री रिनपोछे ने कही है कि जो लोग आज उनका साथ दे रहे हैं वे कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। तिब्बत की इस समस्या के लिए श्री सिन्हा ने भारत के उन नेताओं को जिम्मेदार बताया जो मूक बने खड़े देखते रहे, और चीन तिब्बत को लील गया। श्री सिन्हा ने भारत के नेतृत्व को आगाह किया कि चीन सोची–समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, अगर चीन को हमने अभी ठीक से नहीं समझा तो आने वाले समय में चीन हम सबके लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि चीन की नीयत ठीक नहीं है, चीन अपने स्वभाव के अनुरूप दूसरे देशों के भू–भाग पर बुरी नजर डाल रहा है। आने वाले खतरे को हमने अभी नहीं समझा तो हम बिना किसी लड़ाई के भारत, चीन को सौंपने के लिए मजबूर होंगे। तिब्बत के बाद अब अगला भुक्तभोगी भारत होगा। इसलिए आज भारत को तिब्बत के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। श्री यशवंत सिन्हा ने बताया कि 17 अप्रैल 1959 में दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एक भाषण में कहा था कि दो देशों की दोस्ती का मतलब यह नहीं कि उनमें कभी मतभेद न हो। श्री उपाध्याय ने यह भी कहा था कि भारत कभी महान देश नहीं हो सकता अगर यह क्षमता नहीं कि हम दूसरे की आंख में आंख डालकर देख सकें। उन्होंने कहा कि सरकारें कमजोर होती हैं, जनता कमजोर नहीं होती इसीलिए तिब्बत का जनांदोलन आज जीवित है।

तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री सामदोंग रिनपोछे ने कहा कि इस सम्मेलन ने विश्वास का स्रोत जागृत किया है। यह समूह साधारण नहीं है, क्योंकि इसमें सभी धर्मों व सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के प्रतिनिधियों में अध्यापक, पत्रकार, समाजसेवी, डॉक्टर, व्यापारी, कर्मचारी आदि की उपस्थिति से हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे और तिब्बत को आजादी मिलेगी। उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व में तिब्बत समर्थक वर्ग हमारे निवेदन पर नहीं बने हैं बल्कि अंतरात्मा की आवाज पर सत्य और न्याय की रक्षा के लिए लड़ाई में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री रिनपोछे ने भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रशंसा करते हुए कहा कि तिब्बत समर्थक भारतीय आर्यावर्त भारत वर्ष की न्यायप्रियता के स्वभाव को प्रकट करते हैं। भारत की मूल संस्कृति को बचाते हुए अपनी पृष्ठभूमि पर खड़े होने की क्षमता और साहस को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए विवेक और अंतरात्मा से निर्णय करना है, कि उन्हें तिब्बत की आजादी के लिए क्या करना है यह उनका निवेदन है। उन्होंने कहा कि तिब्बत की समस्या क्या है, संघर्ष का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे समझना आवश्यक है। जब तक सही पहचान नहीं होती, कार्य की दिशा में भटकना राजनीतिक समझदारी नहीं है, तिब्बत का आंदोलन सत्ता का संघर्ष नहीं है। स्वाधीनता की मांग स्वराज प्राप्त करने की प्रक्रिया है, साधन है। संघर्ष सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। अगर ये दो बिंदु जिसके भी दिमाग में नहीं हैं वे तिब्बत के समर्थक नहीं हो सकते। चीन संख्या की दृष्टि से सशक्त राष्ट्र है, जबकि 60 लाख तिब्बत की जनसंख्या बहुत कम है। उन्होने यह भी कहा कि नैतिक सत्य के बल पर हम बराबरी पर खड़े हैं, चीन का हृदय परिवर्तन करके ही स्थाई समाधान खोजेंगे। चीन और भारत के संबंध भी संपूर्ण विश्व की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम नहीं चाहते कि तिब्बत के प्रश्न को लेकर भारत–चीन के संबंधों में कटुता आए। श्री रिनपोछे ने तिब्बतियों का भी आह्वान किया कि बड़े हित के लिए लघु हितों को बलिदान करना नीति विरोधी नहीं, न्याय संगत है। महायान बौद्धधर्म का मूल सिद्धांत है कि बहुजन सुखाय के लिए स्वहित त्यागना ही संपूर्ण जगत के हित में है।

तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री रिनपोछे की इस धारणा के विपरीत आंदोलन के विशेष प्रतिनिधि श्री अनिल गुप्ता ने कहा कि शांति और अहिंसा से हटकर भी चीन को चीन की भाषा में समझाना पड़ेगा। जिसकी मंशा ही हिमालय पर कब्जा करने की हो वह शांति और अहिंसा की भाषा नहीं समझेगा। श्री गुप्ता ने कहा कि सत्य और अहिंसा के साथ

तो भगतसिंह और सुभाष चंद्र बोस भी थे लेकिन क्या हुआ सबके सामने है। सत्र के दूसरे दिन वरिष्ठ पत्रकार श्री नंद किशोर त्रिखा ने कहा कि भारत में तिब्बत समर्थक आजादी के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि तिब्बत की आजादी ही भारत का लक्ष्य और आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तिब्बत की आजादी के इस आंदोलन से भारत का जनमानस इसलिए जुड़ा है कि किसी भी प्रकार से तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए।

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के मनमस्तिष्क में एक ही लालसा है कि तिब्बत आध्यात्मिक शक्ति के रूप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र हो। उन्होंने इस अवसर पर हिमालय परिवार के प्रमुख इंद्रेश कुमार जी का उल्लेख करते हुए कहा कि जब संघ के किसी व्यक्ति ने तिब्बत की आजादी का बीड़ा उठा लिया है तो यह कार्य पूरा होकर ही रहेगा। युवा स्वास्थ्य मंत्री श्री राजीव जिंदल ने कहा कि तिब्बत की सभ्यता और संस्कृति बहुत पुरानी है, इस सत्यता को झुठलाया नहीं जा सकता।

तिब्बत के समर्थन में किसी देश ने आवाज नहीं उठाई यह दुर्भाग्य का विषय है और चीन का विरोध नहीं हुआ यह चिंता का विषय है। गांधी विचारक डॉ. रामजी सिंह ने कहा कि भारत के लिए तिब्बत को विस्मृत करने का मतलब है कैलाश मानसरोवर को विस्तृत करना। भारत – तिब्बत मैत्री संबंध गाढ़ा है, और मौलिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध हैं, जो कभी टूट नहीं सकते। 29 वीं सदी में संकीर्ण राष्ट्रवाद और कट्टरपंथीवाद नहीं चल सकता। वैश्विक दृष्टि से विचार करना होगा, सांप्रदायिक धर्म के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। बुद्ध के पास करुणा छोड़कर कोई हथियार नहीं था, महावीर के पास भी कोई हथियार नही था लेकिन विश्व ने इन दोनों ही महापुरूषों को स्वीकार किया है।

भारत–तिब्बत मैत्री संघ दिल्ली प्रांत के संयोजक व दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जे. पी. शर्मा ने कहा कि पूर्ण आजादी के बगैर सम्मेलन का कोई महत्व नहीं है। इसके लिए संगठन, कार्य और कार्य को कैसे कार्यान्वित करें, इन तीनों को साथ लेकर चलना होगा, तभी तिब्बत की आजादी का लक्ष्य पूरा हो सकता है। श्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि विद्यार्थी संगठन, लाइंस क्लब, मात्र शक्ति जैसे कई संगठनों को आगे आना होगा, तब आजादी का जो लक्ष्य हमने लिया है उसे पूरा करने में संदेह नहीं। उन्होंने कहा कि तिब्बत इतिहास में स्वतंत्र राष्ट्र रहा है। अहिंसा प्रिय देश है। वो सुरक्षित था, इसकी जानकारी से भारत की जनता को अवगत कराना होगा।

दिल्ली की महिला प्रतिनिधि श्रीमती राज शर्मा ने आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा, इतिहास गवाह है कि भारत की आजादी से लेकर अनेक आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सहयोग लिए बगैर आज तक कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ इस बात का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। ❖

राष्ट्र हित में नहीं गौ हत्या : सुदर्शन

राष्ट्रीय सवयंसेवक संघ के सरसंघ चालक कुप सी सुदर्शन ने गो वध को इस देश के लिए सबसे बड़ा कलंक मानते हुए प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह को संसद में गो हत्या बंदी विधेयक लाने की सलाह दी है। विगत 8 जून को नागपुर में तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह में श्री सुदर्शन ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर गो हत्या बंदी विधेयक को बहुमत से पारित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसा कर पांएगे इस पर उन्हें उम्मीद नहीं है।

समारोह में मुख्य अतिथि रामचंद्रपुरा मठ (शिमोगा) के पूज्य स्वामी राघवेश्वर भारती की उपस्थिति में संघ प्रमुख ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि अंग्रेजों के काल में शुरू हुई गौ हत्या स्वाधीनता के बाद भी इस देश में जारी है। श्री सुदर्शन ने बताया कि प्रतिदिन एक लाख गोवंश काटा जा रहा है, और इस समय इस देश में केवल 15 करोड़ गोवंश ही बचा है। उन्होंने कहा कि तुष्टिकरण की शिकार मौजूदा सरकार गो हत्या बंदी विधेयक संसद में पेश करने से इसलिए कतरा रही है, क्योंकि उसे इस बात का खतरा है कि ऐसा करने से उसे मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे। इसी तुष्टिकरण की मानसिकता के चलते हिंदू बहुल इस देश में गौ हत्या के नाम पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

श्री सुदर्शन ने इस अवधारणा को गलत बताया कि मुसलमानों के कारण गौ हत्या बंदी कानून नहीं बन पा रहा, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि दारुल उलूम के अनुसार भी इस्लाम गौ हत्या की इजाजत नहीं देता। हजरत मोहम्मद साहब की हदीश के अनुसार दूध को अमृत और गौ मांस को जहर माना गया है। उन्होंने कहा कि गौ हत्या के लिए केवल मुसलमानों को दोष देना अनुचित है क्योंकि वर्तमान में मुस्लिम समुदाय देश की भावनाओं के साथ सुसंगत हो रहा है, बावजूद इसके गौ हत्या बंदी विधेयक पेश नहीं किया जाना इस बात का परिचायक है कि हमारे देश के राजनीतिज्ञ राष्ट्र हित के बजाय वोट बैंक की राजनीति पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

टीआरपी की दौड़ में अंधे हुए हिन्दी न्यूज़ चैनल

■ पीयूष पांडे

नोएडा के चर्चित आरुषि हत्याकांड से क्या किसी को कोई लाभ हुआ। मासूम आरुषि और तलवार परिवार का नौकर हेमराज अब इस दुनिया में नहीं है। हत्या के आरोप में आरुषि के पिता राजेश तलवार सलाखों के पीछे हैं। जांच में कोताही बरतने के आरोप में आईजी समेत कई पुलिस अधिकारियों का तबादला हो चुका है। इस दोहरे हत्याकांड की वजह से डॉक्टर तलवार के पड़ोसी कई दिनों तक अलग परेशान रहे क्योंकि सीबीआई ने गाहे–बगाहे कभी भी किसी से भी पूछताछ कर डाली। लेकिन, इस दोहरे हत्याकांड से मीडिया, खासकर हिन्दी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बांछें खिल गईं। पंद्रह मई को हत्या के बाद से हिन्दी न्यूज़ चैनलों को देश के सबसे अहम मसलों में आरुषि हत्याकांड ही लगा, और इस हत्याकांड से जुड़ी खबरों को मसाला लगाकर प्राइम टाइम में खूब दिखाया गया।

लेकिन सवाल सिर्फ ख़बर दिखाने का भर का नहीं है। हिन्दी न्यूज़ चैनलों में पसरी उस संवेदनहीनता का है, जिसने एक मासूम लड़की की हत्या को बाज़ार का माल बना दिया। फिर, इस माल को स्केच, नाट्य रुपांतरण और सूत्रों के हवाले से जैसे नाम देते हुए इस तरह दर्शकों के सामने परोसा कि सब कुछ चैनलों को ही पता है।

बात सिर्फ, आरुषि–हेमराज हत्याकांड की ख़बर तक सीमित होती तो भी समझा जा सकता था। हिन्दी न्यूज चैनलों को आरुषि से मिलने वाली टीआरपी का ऐसा लोभ लगा कि उसके इर्द–गिर्द विशेष कार्यक्रम बुन दिए गए। हद तो ये कि टीआरपी की चूहा दौड़ में हाल में नंबर वन हुए एक चैनल ने अपने कार्यक्रम में बाप–बेटी के रिश्तों पर ही सवाल उठा डाले। चैनल ने कार्यक्रम के दौरान एक बेटी के हवाले से कहा कि उसे अपने पिता से डर लगने लगा है। चैनल ने फोन लाइन खोलते हुए घर में रहने वाली लड़कियों से कहा कि यदि उन्हें भी अकेले घर में अपने पिता से डर लगता हो तो वों फोन करें। इस तरह के कार्यक्रम का क्या मतलब है? राजेश तलवार ने आरुषि–हेमराज की हत्या की है या नहीं–ये अभी भी साबित नहीं हुआ है। लेकिन मीडिया ट्रायल में डॉक्टर तलवार को दोषी साबित कर दिया गया। दुर्भाग्यजनक बात ये कि इस तथ्य को आधार बनाकर कई मासूम बच्चियों के दिलों में अपने पिता के लिए ज़हर खोलने की कोशिश की गई।

दरअसल, आरुषि हत्याकांड से जुड़ी कवरेज तो एक अदद उदाहरण भर है। टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट यानी टीआरपी की गलाकाट दौड़ में हिन्दी न्यूज चैनल उस स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें कुछ भी गलत नहीं दिखता। न्यूज़ चैनलों का एंकर सांईं बाबा के प्रगट होने की ख़बर को उसी आत्मविश्वास से दर्शकों को बताता है, जिस भरोसे से लेफ्ट के समर्थन वापस लेने की। आस्था की टीआरपी में डुबकी लगाते किसी चैनल को बोलते सांईं बाबा की तसवीर दिखाने से परहेज नहीं, तो दूसरे के लिए उस वक्त सबसे अहम खबर उस खबर को गलत साबित करना होती है। आस्था की टीआरपी कितनी जोरदार है, इसकी बानगी 27 जून को सबसे तेज़ चैनल के एक कार्यक्रम में भी दिखी।

इस दिन शाम के वक्त सोनीपत में सांई बाबा के एक घर में प्रगट होने की खबर चैनल पर दिखायी जा रही थी। लेकिन असंवेदनशीलता का आलम देखिए कि इसी प्रोग्राम के दौरान ब्रेकिंग न्यूज की पट्टी पर ख़बर चल रही थी – अंडमान में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता। 6.7 तीव्रता वाला भूकंप कम नहीं होता लेकिन चैनल पर सांई प्रगट हुए हों तो कार्यक्रम बीच में रोककर इस महत्वपूर्ण ख़बर के बारे में दिखाने की हिम्मत कौन उठाए?

दिक्कत ये है कि इन ख़बरों को दिखाते वक्त ज्यादातर चैनल और उनके एंकर सिर्फ मीडियम भर नहीं होते बल्कि ऐसी खबरों को जस्टिफाई भी करते दिखते हैं।

वैसे टीआरपी की दौड़ में आरुषि से लेकर सांईं तक सब एक फॉर्मूला ही हैं, जिसे हिन्दी न्यूज चैनल लगातार आजमाते रहते हैं।

बहरहाल, हिन्दी न्यूज़ चैनलों से ख़बर गायब हैं। टीआरपी की मारामारी में ब्रेकिंग न्यूज़ अपनी अहमियत पहले ही खो ही चुकी थी। कभी 9–11 या संसद पर हमला जैसी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हुआ करती थीं, आज कमिश्नर का कुत्ता खोने और बिग बी को ठंड लगने जैसी फालतू खबरें इस कैटेगरी में शामिल हो चुकी हैं। हिन्दी न्यूज़ चैनलों को अब हर हाल में टीआरपी चाहिए। इसके लिए चाहे हर घर में एक आरुषि बने या हर घर में सांईं प्रकट हों–उनकी बला से!

ईमेल : pandeypiyush07@gmail.com